https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'भारत की विकास यात्रा आगे बढ़ती रहेगी'

वर्ष-13, अंक-02 16-31 जनवरी, 2018 (पाक्षिक) ₹20

गुजरात व हिमाचल प्रदेश में बनी भाजपा सरकार

विजय रूपाणी और जय राम ठाकुर ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

हमें पुरुषार्थ करना होगा

चुनावी बॉन्ड क्यों ज़रूरी?

तीन तलाक पर कांग्रेस का धोखा

गांधीनगर (गुजरात) में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते श्री विजय रूपाणी

शिमला (हिमाचल प्रदेश) में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते श्री जय राम ठाकुर

शपथ ग्रहण समारोह के समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का स्वागत करते श्री विजय रूपाणी

जनाभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह और श्री जय राम ठाकुर

गांधीनगर, गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते भाजपा के वरिष्ठ नेतागण

शिमला में शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **गुजरात : विजय रूपाणी ने दूसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ**
गुजरात में 26 दिसंबर को लगातार छठी बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली ने श्री विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद एवं...

वैचारिकी
हमें पुरुषार्थ करना होगा 17

श्रद्धांजलि
राजमाता विजया राजे सिंधिया 19

लेख
चुनावी बॉन्ड क्यों ज़रूरी? 20
तीन तलाक पर कांग्रेस का धोखा 22
मातृ शक्ति को सलाम 24

अन्य
स्मार्ट शहरी मिशन के तहत 1872 करोड़ रुपये की 148 परियोजनाएं पूरी 15
विदेशी मुद्रा भंडार 409 अरब डालर के नये रिकॉर्ड स्तर पर 21
'ग्रामीण, कृषि क्षेत्र में सरकार 2,90,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है' 23
विश्वस्तरीय रिसर्च पर केंद्र सरकार का जोर 25
लोकसभा में 13 विधेयक और राज्यसभा में 9 विधेयक पारित 26
सेवा क्षेत्र की दूसरी तिमाही के दौरान 7.1 प्रतिशत की वृद्धि 27
'जनता कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार को स्वीकार करने के... 29
भारत की विकास यात्रा आगे बढ़ती रहेगी: नरेंद्र मोदी 30
यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत 25 पायदान ऊपर पहुंचा 32

स्थायी स्तंभ
सोशल मीडिया से 04
पत्र-पत्रिकाओं से 33
स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

11 **जनता ने 2018 में कांग्रेस सरकार की विदाई करने का मन बना लिया है : अमित शाह**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री...

13 **'त्रिपुरा 25 साल के भ्रष्ट माकपा सरकार में पिछड़ गया है'**
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 7 जनवरी को अगरतला में विजय संकल्प...

सरकार की उपलब्धियां

14 **लोकसभा में पारित हुआ महत्वपूर्ण 'तीन तलाक' बिल**
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक साथ 'तीन तलाक' पर रोक लगाने वाले विधेयक...

16 **भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश**
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से भारत...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

जब लोग कुछ तय कर लेते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। 125 करोड़ भारतीय हमारे देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।

@AmitShah

क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा व उनके सम्मान के लिए जीवन भर कार्य किए। महिला विरोधी कुरीतियों को ध्वस्त कर महिलाओं के सम्मान की जो परिभाषा उन्होंने रची है, वह सदियों तक हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। ऐसी महान समाजसेविका की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन।

@rsprasad

जब केरल और कर्नाटक में हमारे आरएसएस स्वयंसेवक की हत्या होती है, तो राहुल गांधी उस पर क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस ने इस देश में सबसे लंबे समय तक घृणा की राजनीति की है।

facebook

प्रदेश के हर नागरिक को हरसंभव लाभ पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए हमने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। इलाज को सस्ता व त्वरित बनाने के साथ-साथ लोगों को अधिकाधिक स्वास्थ्य सेवाओं के अवसर प्रदान कराने के मकसद से सृजित यह योजना आज प्रत्येक वर्ग के लोगों की ज़िंदगियां बदल रही है। मिटेगा हर मर्ज़, बिना किसी क़र्ज़!

— **वसुंधरा राजे**

ओंकारेश्वर वेदान्त दर्शन के अद्भुत केंद्र के रूप में स्थापित होगा। आदिशंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित कर उनके योगदान को चिरस्मरणीय बनाया जाएगा।

— **शिवराज सिंह चौहान**

भारत में गरीबी, अराजकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। इन समस्याओं से देश को हर हाल में मुक्त किया जाएगा। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा, ताकि देश का विकास हो और एकता एवं अखडण्ता प्रबल रूप से विकसित हों।

— **योगी आदित्यिनाथ**

'कमल संदेश' की ओर से
सुधी पाठकों को
गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

तीन तलाक विधेयक :
कांग्रेस की दोहरी मानसिकता का शिकार

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने के बाद भी इसके दोषियों के लिए दंड के प्रावधान करने वाले विधेयक को संसद में पारित नहीं कराया जा सका।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 पर राज्यसभा में लगातार अड़ंगा लगाया गया और अंततः यह पारित नहीं हो पाया। लोकसभा में जहां कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध नहीं किया, इसके ठीक विपरीत राज्यसभा में इसे 'प्रवर समिति' में भेजने के बहाने इसे रोका गया। सरकार ने ठीक ही कांग्रेस के इस चाल पर न झुकने का निर्णय लिया तथा इस विषय पर कांग्रेस की दोहरी नीति को जनता के सामने उजागर कर दिया। इससे मुस्लिम महिलाओं की न्याय की लड़ाई और भी अधिक लंबी हो गई है तथा कांग्रेस के इस ढोंग के कारण वे अपने उचित अधिकार से वंचित हो गई हैं।

देश में मुस्लिम महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए संघर्षों के लंबे दौर से गुजरना पड़ा है तथा सर्वोच्च न्यायालय में संविधान प्रदत्त समानता के उनके वाजिब दावों पर मुहर लगवाने में उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है। तीन तलाक पर उनकी लंबी लड़ाई की यह वास्तविक परिणति ही है कि इस प्रथा के असंवैधानिक घोषित होने के बावजूद इसको चलाने वाले लोगों के लिये कठोर दंड के कानूनी प्रावधान हों। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया है, परन्तु तीन तलाक की घटनाएं अब भी घट रही हैं और इस पर कोई कानूनी दंडात्मक प्रावधान नहीं होने के कारण प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा। ऐसी पीड़ित महिलाओं एवं उनके बच्चों के भरण–पोषण आदि इस प्रश्न के अन्य पहलू हैं, जिस पर तुरंत कानूनी प्रावधान की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस विधेयक से इन सब समस्याओं के हल निकलने की उम्मीद थी, परन्तु कांग्रेस जिसने लोकसभा में इस विधेयक का विरोध नहीं किया था, अंततः घबरा गई और राज्यसभा में इसे रोक दिया। कांग्रेस नेताओं ने तीन तलाक देने वाले दोषी पतियों के कारावास की सजा पर हास्यास्पद तरीके से सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि ऐसे करने से पीड़ित महिला एवं उनके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। यदि इस तर्क को मान लिया जाए तब तो किसी भी दोषी को सजा देना कठिन हो जाएगा तथा पुरुषों को अपनी पत्नियों पर जुल्म ढाने का लाइसेंस मिल जाएगा। तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायाल्य के निर्णय की यह तर्कसंगत परिणति है कि दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड के प्रावधान हों तथा महिलाओं के लिए समाज में एक सकारात्मक वातावरण बने। पर कांग्रेस और उसके सहयोगी अपनी इन जिम्मेदारियों से विमुख हो गये तथा मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये लाये गए इस विधेयक पर अपना कर्तव्य नहीं निभा पाये।

> मजहब के नाम पर समाज के पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले वर्ग के तुष्टिकरण की राजनीति के स्थान पर महिला–सशक्तिकरण पर ठोस पहल का स्वागत हो रहा है। एनडीए सरकार के सुधारात्मक कदमों के कारण आज मुस्लिम महिलाएं 'महरम' के बैगर हज पर जा सकती हैं। यह बहुत ही बड़ा और स्वागत योग्य परिवर्तन है।

पूरा देश एक व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह परिवर्तन इस बात से प्रमाणित होता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो मामले में निर्णय के विपरीत तीन तलाक पर हुए निर्णय का मुस्लिम समाज ने अधिकांशतः स्वागत किया है। मजहब के नाम पर समाज के पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले वर्ग के तुष्टिकरण की राजनीति के स्थान पर महिला–सशक्तिकरण पर ठोस पहल का स्वागत हो रहा है। एनडीए सरकार के सुधारात्मक कदमों के कारण आज मुस्लिम महिलाएं 'महरम' के बैगर हज पर जा सकती हैं। यह बहुत ही बड़ा और स्वागत योग्य परिवर्तन है। हमारे देश में जाति, पंथ, मजहब से परे बड़े परिवर्तनों एवं सुधारों के लिये बड़े निर्णयों की आवश्यकता है, ताकि एक न्यायपूर्ण एवं समरस समाज की स्थापना हो सके जिसका सपना हमारे संविधान के निर्माताओं ने देखा था। कांग्रेस तथा इसके सहयोगी दलों को अपने राजनैतिक निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जल्द से जल्द इस विधेयक को पारित करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

विजय रूपाणी ने दूसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

गुजरात में 26 दिसंबर को लगातार छठी बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली ने श्री विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनके अलावा 19 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई।

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह समेत कई केन्द्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सहित कई विशिष्टजन उपस्थित थे। समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल, श्री शंकर सिंह वाघेला एवं श्रीमती आनंदी बेन पटेल भी उपस्थित थे। 18 राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री उपस्थित रहे।

श्री रूपाणी के अलावा नौ अन्य ने कैबिनेट मंत्रियों के तौर पर शपथ ली। इनमें उपमुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल भी हैं। 10 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। नौ कैबिनेट मंत्रियों और 10 राज्य मंत्रियों में से पांच–पांच पहले भी मंत्री थे। श्री रूपाणी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले वह 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री बनाए गए थे। गौरतलब है कि राज्य में 1995 से भाजपा की सरकार है।

श्री रूपाणी और श्री पटेल को 22 दिसंबर को हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में क्रमश: नेता और उपनेता चुना गया था। शपथ ग्रहण से पहले श्री रूपाणी और श्री पटेल ने समारोह में शाामिल होने आए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अभिवादन किया।

भाजपा एवं राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी को शुभकामना दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी ने श्री विजय रूपाणी को बधाई दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भी नई सरकार को शुभकामनाएं दीं।

@rajnathsingh

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री विजय रूपाणी के शपथ–ग्रहण समारोह में भाग लिया। मुझे विश्वास है कि गुजरात श्री रूपाणी के नेतृत्व में विकास और समृद्धि की राह में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।

@arunjaitley

श्री विजय रूपाणी तथा श्री नितिन भाई पटेल द्वारा क्रमशः गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ–ग्रहण पर हार्दिक बधाई। श्री विजय रूपाणी और श्री नितिन भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात एवं यहां के लोग निरंतर नई ऊंचाइयां छू सकेंगे।

विजय रूपाणी : जीवन परिचय

श्री विजय रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 में हुआ। वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं गुजरात के मुख्यमंत्री है। वह राजकोट पश्चिम से गुजरात विधानसभा में प्रतिनिधि हैं।

वह रंगून, बर्मा (अब यांगोम, म्यांमार) में जन्मे; श्रीमती मायाबेन और श्री रमणीक लाल रूपाणी के सातवें तथा सबसे छोटे पुत्र हैं। बर्मा के राजनीतिक अस्थिरता के कारण वह अपने परिवार सहित राजकोट में चले आए। उन्होंने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से धर्मेन्द्र सिंह जी कला कालेज से बीए और एलएलबी का अध्ययन किया।

श्री विजय रूपाणी ने अपना सार्वजनिक जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में शामिल हुए और उसके बाद 1971 में जनसंघ से जुड़े। 1976 में आपातकाल के समय भुज और भाव नगर में 11 महीने जेल में रहे। वे 1978 से 1981 तक रा.स्व.सं. के प्रचारक रहे। 1987 में वह राजकोट नगर निगम (आरएमसी) के पार्षद निर्वाचित हुए और इस दौरान वह ड्रेनेज समिति के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1996 से 1997 तक राजकोट के महापौर के रूप में सेवा की। 1998 में वह भाजपा के गुजरात इकाई के महासचिव रहे। 2006 में वह गुजरात पर्यटन के चेयरमैन रहे। 2006 से 2012 तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने भाजपा गुजरात इकाई के महासचिव के रूप में चार बार भूमिका निभाई और वे श्री नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री के दौरान 2013 में गुजरात म्युनिसिपिल वित्त बोर्ड के चेयरमैन रहे।

19 फरवरी 2016 को श्री रूपाणी राज्य भाजपा के अध्यक्ष बन गए। नवम्बर 2014 में आनन्दी बेन पटेल सरकार के प्रथम कैबिनेट विस्तार में उन्हें मंत्री पद दिया गया और वे परिवहन, जल आपूर्ति श्रम और रोजगार मंत्री बने। वह फरवरी 2016 से अगस्त 2016 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे।

मुख्यमंत्री के रूप में वे श्रीमती आनन्दी बेन पटेल के उत्तराधिकारी बने और 7 अगस्त 2016 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्हें 22 दिसम्बर 2017 को विधानसभा पार्टी का नेता चुना गया और वे वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं।

मंत्रिमंडल

मुख्यमंत्री
श्री विजयभाई आर. रूपाणी
सामान्य प्रशासन, उद्योग, गृह, शहरी विकास, बंदरगाह, खान और खनिज, सूचना और प्रसारण, पेट्रोलियम, जलवायु परिवर्तन, योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सभी नीतियां और सभी मामले, जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए।

उपमुख्यमंत्री
श्री नितिनभाई पटेल
वित्त, सड़क और भवन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, नर्मदा, कल्पसार, कैपिटल प्रोजेक्ट

कैबिनेट मंत्री
श्री रणछोड़भाई चानाभाई फाल्दू
कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, पशुपालन, परिवहन

श्री भूपेंद्र सिंह मनुभाई चूड़ासमा
शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक और प्रौढ़), उच्च और तकनीकी शिक्षा, कानून और न्याय, विधान और संसदीय मामले, नमक उद्योग, गाय-प्रजनन और नागरिक उड्डयन

श्री कौशिकुमार जमनादास पटेल
राजस्व

श्री सौरभ पटेल
ऊर्जा

श्री गणपतभाई वेस्ताभाई वसावा
आदिवासी विकास, पर्यटन, वन, महिला और बाल कल्याण

श्री जयेश रादडिया
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, कुटीर उद्योग, छपाई और लेखन सामग्री

श्री दिलीपकुमार विराजी ठाकुर
श्रम और रोजगार, आपदा प्रबंधन, देवस्थान, तीर्थयात्रा विकास

श्री ईश्वरभाई (अनिल) रमणभाई परमार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता (अनुसूचित जाति का कल्याण, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का कल्याण सहित)

राज्यमंत्री
श्री प्रदीपसिंह भागवतसिंह जडेजा
गृह, ऊर्जा, विधान और संसदीय मामले, कानून और न्याय, (राज्य मंत्री) पुलिस आवास, सीमा सुरक्षा, सिविल रक्षा, ग्राम रक्षक दल, जेल, प्रोहिबिशन एक्साइज, स्वैच्छिक संगठनों का समन्वय, गैर-निवासी गुजराती, प्रोटोकॉल (सभी स्वतंत्र प्रभार)

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
सिंचाई, जल आपूर्ति (स्वतंत्र प्रभार)

श्री परषोत्तमभाई उधवजीभाई सोलंकी
मत्स्य पालन

श्री बचुभाई मगनभाई खाबड
ग्रामीण आवास, ग्रामीण विकास, पशुपालन, गाय प्रजनन

श्री जयद्रथसिंहजी चंद्रसिंहजी परमार
कृषि (राज्य मंत्री) पंचायत, पर्यावरण (स्वतंत्र प्रभार)

श्री ईश्वरसिंह ठाकोरभाई पटेल
सहयोग, खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन (राज्य मंत्री)

श्री वासनभाई गोपालभाई अहिर
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का कल्याण

श्रीमती विभावरीबेन विजयभाई दवे
महिला और बाल कल्याण, शिक्षा (प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा) और तीर्थयात्रा

श्री रमनलाल नानुभाई पाटकर
वन और जनजातीय विकास

श्री किशोर कानानि (कुमार)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा

जय राम ठाकुर बने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री

गत 27 दिसंबर को शिमला स्थित ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित समारोह में भाजपा नेता श्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री ठाकुर के साथ मंत्रिमंडल के 11 अन्य मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 52 वर्षीय श्री जय राम ठाकुर और मंत्रियों को पद और गोनीयता की शपथ दिलाई। स्वयं सेराज से छठी बार भाजपा विधायक चुने गए श्री ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल में छह नए चेहरों को शामिल किया।

मुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही 12 सदस्यीय कैबिनेट की संख्या पूरी हो गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा सहित अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसके अतिरिक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़णवीस, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह समेत कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे।

@narendramodi

श्री जय राम ठाकुर और उन सभी को बधाई, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण में भाग लिया। मुझे विश्वास है कि इस बार टीम अथक कार्य करेगी और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए असाधारण परिश्रम से उनकी सेवा करेगी।

@AmitShah

हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर जी और उनके मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा सरकार देवभूमि हिमाचल के गौरव को बहाल करने के लिए कड़ा परिश्रम कर लोगों की सेवा करेगी।

@arunjaitley

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करने पर श्री जय राम ठाकुर जी को हार्दिक बधाई। एक सफल कार्यकाल पूरा करने के लिए उनकी मंत्रिपरिषद को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित हैं।

जय राम ठाकुर : जीवन परिचय

श्री जय राम ठाकुर का जन्म 6 जनवरी 1965 में हुआ और वे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रदेश के चौदहवें मुख्यमंत्री हैं। 24 दिसम्बर 2017 को वे भाजपा विधानसभा के नेता चुने गए। 1998 से वे हिमाचल प्रदेश के विधायक हैं और इससे पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। 2009 से 2012 तक वे ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री रहे। इस बार वे मंडी में सिराज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं।

उनका जन्म निर्धन परिवार में हुआ और उनकी दो बहनें तथा तीन भाई हैं। उन्होंने मंडी में अपनी स्कूली शिक्षा गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल बागीशियड से की तथा उसके बाद वल्लभ गवर्नमेंट कालेज से बीए की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने चण्डीगढ़ से पंजाब विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त की।

वह वल्लभ गवर्नमेंट कालेज मंडी से स्नातक बने और वे एबीवीपी में शामिल हुए। वह 1986 में एबीवीपी के प्रांत सहमंत्री, 1989–95 में भारतीय जनता पार्टी (जम्मू–कश्मीर) के संगठन मंत्री, 1993–95 में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और 2006–09 में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। 1998 में वे राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और चचियोट विधानसभा क्षेत्र में 2003 और 2007 में पुनः निर्वाचित हुए, जिसका नाम डिलिमिटेशन के बाद बदला गया। उन्हें जनरल डेवलेपमेंट कमिटी और शिक्षा समिति का चेयरमैन बनाया गया; और वे प्रदेश सिविल आपूर्ति कार्पोरेशन लि. के वाइस–चेयरमैन रहे। वे ग्रामीण योजना समिति के चेयरमैन भी रहे और 2012 में पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में विभिन्न हाउस समितियों के सदस्य रहे।

वे दिसम्बर 2012 में लगातार चौथी बार प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए।

मंत्रिमंडल

जय राम ठाकुर
मुख्यमंत्री
वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह, योजना, कार्मिक एवं अन्य सभी विभाग जो आबंटित नहीं किये गये हैं

महेंद्र सिंह
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, बागवानी, सैनिक कल्याण मंत्री

किशन कपूर
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, चुनाव मंत्री

सुरेश भारद्वाज
उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, संसदीय कार्य, कानून एवं कानूनी यादगार मंत्री

अनिल शर्मा
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री

सरवीन चौधरी
शहरी विकास, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग मंत्री

राम लाल मार्कंडा
कृषि, जनजातीय विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री

विपिन सिंह परमार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री

वीरेंद्र कंवर
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य पालन मंत्री

बिक्रम सिंह
उद्योग, श्रम एवं रोजगार, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री

गोविंद सिंह
वन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री

राजीव सैजल
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सहयोग मंत्री

जनता ने 2018 में कांग्रेस सरकार की विदाई करने का मन बना लिया है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 6 जनवरी को मेघालय के गारो हिल्स स्थित टिकरीकेला में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से मेघालय को विकास से महरूम रखने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार को 2018 में उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।

मेघालय की जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए श्री शाह ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि 2018 पूरे देश के लिए शांति व समृद्धि लाने वाला हो, लेकिन मुझे मेघालय को विशेष बधाई देनी है क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रदेश की जनता ने 2018 में कांग्रेस सरकार की विदाई करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि 2018 में मेघालय से भ्रष्ट कांग्रेस सरकार जाने वाली है और 'सबका साथ, सबका विश्वास' के सिद्धांत पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि मेघालय से कांग्रेस सरकार के जाने का मतलब मेघालय से भ्रष्टाचार की विदाई होने वाली है और प्रदेश में डेवलपमेंट पहुंचने वाला है, मेघालय पूरे देश में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है, हेल्थ सुविधाओं का विकास होने वाला है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होने वाला है और यहां के युवाओं को रोजगार मिलने वाला है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा मेघालय के विकास के लिए, यहां के लोगों की भलाई के लिए जो पैसा भेजा जाता है, वह प्रदेश की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद कांग्रेसी नेताओं के भ्रष्ट आलीशान बंगलों की जगह मेघालय वासियों

के घर बनने की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 हर तरह से मेघालय के लिए अच्छा ही होने वाला है।

श्री शाह ने कहा कि 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से नार्थ-ईस्ट के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा नार्थ-ईस्ट के डेवलपमेंट को टॉप-मोस्ट प्रायोरिटी पर रखा है। उन्होंने कहा कि 40 साल बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शिलांग में नार्थ-ईस्ट काउंसिल (NEC) की बैठक कर एक नई परंपरा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक नई व्यवस्था तैयार की है जिसके तहत हर 15 दिन में कोई न कोई केन्द्रीय मंत्री पूर्वोत्तर के एक राज्य में जायेंगे और वहां पर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट को रोड, रेलवे और आईटी कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के गठन के कुछ महीनों बाद नवंबर, 2014 में मेघालय में सबसे पहली रेलवे लाइन लाने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पूरे नार्थ-ईस्ट के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले नॉर्थ-ईस्ट के स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते थे, तो उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन दिल्ली में नार्थ-ईस्ट के 425 छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल बनाने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया गया है। हेलिकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी बहाल करने की योजना के बाद मेघालय -अरुणाचल प्रदेश को रेलवे से भी जोड़ने पर तेज गति से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेघालय में दूरसंचार के विकास सहित पूरे पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिए लगभग 5300 करोड़ रुपये दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि हजारों मेगावाट विद्युत् उत्पादन की 16 नयी योजनायें लाई गई हैं और नॉर्थ-ईस्ट डेवलपमेंट समिट का भी आगाज किया गया है।

श्री शाह ने कहा कि मैं मेघालय की जनता से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में 15 सालों से कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद मेघालय का विकास क्यों नहीं हो पाया, कनेक्टिविटी की योजनाओं पर काम क्यों नहीं हो पाया, मेघालय की जनता को इस वर्ष फरवरी में कांग्रेस के 15 सालों के कुशासन और भ्रष्टाचार का हिसाब मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा जी गारो हिल्स क्षेत्र से ही चुनकर आते हैं, लेकिन उन्होंने यहां के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेघालय में 15 साल तक शासन किया है, 15 साल किसी भी प्रदेश के लिए बहुत बड़ा समय होता है, इन 15 सालों में देश के बाकी राज्य विकास में कहां से कहां पहुंच गए, जबकि मेघालय विकास में आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला गया। उन्होंने कहा कि मेघालय में अभी भी शुद्ध पीने का पानी नहीं है, अस्पताल नहीं हैं, अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं हैं, सस्ती दवाओं की दुकान नहीं है। उन्होंने कहा कि मेघालय की कांग्रेस सरकार 2015-16 के हेल्थ बजट का 76% पैसा खर्च ही नहीं कर पाई, यह पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उन्होंने कहा कि मेघालय के 56% हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो मेघालय दुनिया भर के टूरिस्ट्स के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन हो सकता है, ऐसे प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर मेघालय में इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी समुचित विकास नहीं किया गया, कांग्रेस ने 15 सालों में मेघालय को बर्बाद कर के रख दिया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेघालय की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य में विकास की गति को धीमा करने और जन-कल्याण से मुंह मोड़ने वाली कांग्रेस सरकार को इस बार के विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का समय आ गया है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार मेघालय सहित पूरे पूर्वोत्तर के विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो राज्य का विकास डबल इंजन की स्पीड से हो सकेगा। ■

किरन रिजिजू नागालैंड एवं हेमंत विश्व सरमा बने त्रिपुरा चुनाव प्रभारी

भारतीय जनता पार्टी ने 23 दिसंबर को नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी श्री अरुण सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी कर संगठनात्मक नियुक्ति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू को आगामी नागालैंड विधानसभा चुनाव प्रभारी एवं असम सरकार में वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हेमंत बिश्व सरमा को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। गौरतलब है कि दोनों राज्यों में मार्च और अप्रैल में चुनाव होने हैं। ■

'त्रिपुरा 25 साल के भ्रष्ट माकपा सरकार में पिछड़ गया है'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 7 जनवरी को अगरतला में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश की माकपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्री शाह ने कहा, 'हम हिंसा से नहीं डरते। आप (सीपीएम) हिंसा का कीचड़ जितना फैलाएंगे, कमल उतना ही बेहतर खिलेगा।' इसके साथ ही श्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां भी सरकार बनाने जा रही है।

श्री शाह ने कहा कि त्रिपुरा सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वर्तमान माकपा सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी अब बच नहीं पाएंगे। अगर वे जमीन के अंदर भी छिप गए तो हम जमीन खोदकर उन्हें बाहर निकाल लाएंगे।

श्री शाह ने बेरोजगारी और स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी त्रिपुरा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 37 लाख की आबादी में से 7 लाख लोग बेरोजगार सूची में पंजीकृत हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी खस्ताहाल हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में विकास के नाम पर यहां की सरकार ने बस यही किया है।

भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा 25 साल के भ्रष्ट माकपा सरकार में पिछड़ गया है। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में त्रिपुरा को आदर्श और विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। श्री शाह ने कहा कि जब तक राज्य में माकपा सरकार है, यहां विकास संभव नहीं है। जहां भी माकपा की सरकार होती है वहां गरीबी होती है और बेरोजगारी होती है। जहां भाजपा की सरकार होती है, वहां विकास होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा त्रिपुरा में एक ऐसी सरकार देना चाहती है जो त्रिपुरा की महान परंपराओं, उसकी संस्कृति, राज्य के महानायकों और जननायकों को सम्मान देने का काम करे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि त्रिपुरा की माकपा सरकार, गरीबों को गरीब बनाए रखना चाहती है। ताकि वह उनका वोटबैंक की तरह इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य की आगामी विधानसभा चुनाव मैदान में केवल तीन पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भाजपा हैं। कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दुनिया में समाप्त हो गई है और कांग्रेस पूरे देश में। ऐसे में त्रिपुरा की जनता का वोट 'सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम करने वाली भाजपा को जाना चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि त्रिपुरा में हर साल होने वाले अपराधों में अधिकांश माताओं और बहनों के खिलाफ होते हैं। हम त्रिपुरा की माताओं और बहनों की स्थिति को बदलना चाहते हैं। इसलिए राज्य में भाजपा सरकार का आना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि रोज वैली चिटफंड से लेकर ऐसे भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं जिसमें प्रदेश सरकार आकंठ डूबी हुई है। यदि मुख्यमंत्री चिटफंड के गुनाहगारों को पकड़ना शुरू करें, तो उनका पूरा मंत्रिमंडल जेल में दिखाई देगा। ■

लोकसभा में पारित हुआ महत्वपूर्ण 'तीन तलाक' बिल

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक साथ 'तीन तलाक' पर रोक लगाने वाले विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया। दरअसल, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 को लोकसभा में 28 दिसंबर को वोटिंग कराई गई और अधिकतर सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। तीन तलाक विधेयक पर कांग्रेस का भी साथ मिला। कांग्रेस ने तीन तलाक विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक विवाहित मुस्लिम महिलाओं के हक में है इस विधेयक में संशोधन को लेकर विपक्ष के कई प्रस्ताव खारिज हो गए। एमआईएम के सांसद श्री असद्दुदीन ओवैसी का प्रस्ताव 2 वोटों के मुकाबले 241 मतों के भारी अंतर से खारिज कर दिया गया।

यह विधेयक सिर्फ तलाक-ए-बिद्दत यानी एक साथ तीन तलाक पर ही लागू होगा। यह विधेयक एक साथ तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं को मजिस्ट्रेट के पास जाने की ताकत देता है और अपनी एवं बच्चों की सुरक्षा एवं जरूरतों की मांग करने का हक देता है। इसके अलावा पीड़िता मजिस्ट्रेट से अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी भी मांग सकती है। इस विधेयक के मुताबिक किसी भी तरह से दिया गया एक साथ तीन तलाक, मौखिक, लिखित, ईमेल, मेसेज या वॉट्सऐप, अवैध और अमान्य होगा। इस विधेयक में एक साथ तीन तलाक का दोषी पाए जाने पर पुरुष को तीन साल की कैद की सजा का प्रावधान है।

कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। सरकार मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए इस बिल को लाई है। सदन में तीन तलाक बिल पर सवालों के जवाब में श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आया है। हम शरीयत में दखल देने के लिए तीन तलाक बिल बिल नहीं लाए हैं। पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों में भी तीन तलाक पर रोक है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को मुस्लिम बहनें देख रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर मुस्लिम बेटियों और बहनों के अधिकारों के लिए हम सबको एक आवाज में बोलना चाहिए। आज मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है।

भाजपा सांसद और मंत्री श्री एमजे अकबर ने कहा कि इस्लाम खतरे में है, ये नारा आजादी से पहले देश को बांटने के लिए लगाया जाता था, आज भी यही कहकर समाज में ज़हर फैलाया जा रहा है। दरअसल ट्रिपल तलाक के खिलाफ़ क़ानून से मुस्लिम मर्दों की जबरदस्ती खतरे में है।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ट्वीटर पर इस बिल के विषय में कहा कि यह "तुष्टिकरण के बिना सशक्तिकरण" है।

मुस्लिम महिलाओं के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों की विजय है 'तीन तलाक' विधेयक: अमित शाह

एक साथ 'तीन तलाक' विधेयक लोकसभा में पारित होने पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि ट्रिपल तलाक बिल-द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल, 2017 को संसद में सफलतापूर्वक पारित कराने और ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और केंद्र की पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूं।

श्री शाह ने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। मैं सभी सहयोगी सांसदों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस विधेयक को अपना समर्थन किया है। यह मुस्लिम महिलाओं के जीवन में आशा और सम्मान का नया युग लाएगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ट्रिपल तलाक बिल का लोक सभा से पारित होना मुस्लिम महिलाओं के समानता और मूलभूत संवैधानिक अधिकारों की विजय है। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही सभी पीड़ित महिलाओं के हक़ में तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में लोक सभा द्वारा ट्रिपल तलाक विधेयक पारित होने पर उन्हें बधाई देता हूं।

उन्होंने कहा कि आज से देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वाभिमान पूर्ण एवं समानता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। पार्टी मुस्लिम महिलाओं को मिले उनके अधिकारों एवं सम्मान का स्वागत करती है तथा इसे संकल्पवान 'न्यू इंडिया' के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ते हुए कदम के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार महिलाओं के सम्मान व उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कृत-संकल्पित है। हमारा स्पष्ट मानना है कि धर्म अथवा सम्प्रदाय के आधार पर मुस्लिम माताओं-बहनों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।

विधेयक पारित होने के बाद मुंबई से तीन तलाक की पीड़िता नूरजहां ने कहा, 'यह मुस्लिम महिलाओं की जीत है। वे इसके लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही थीं। यह समस्या के निवारण के लिए बहुत कारगर साबित होगा।' ■

स्मार्ट शहरी मिशन के तहत 1872 करोड़ रुपये की 148 परियोजनाएं पूरी

आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्मार्ट शहरी मिशन के तहत 1,35,958 करोड़ रुपये की 2,864 परियोजनाएं लागू होने के विभिन्न चरणों में हैं। 1872 करोड़ रुपये की 148 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 15,600 करोड़ रुपये की 407 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 13,514 करोड़ रुपये की 237 परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1,02,260 करोड़ रुपये की 2,025 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं। परियोजनाओं को लागू करने के तहत स्मार्ट समाधान, स्मार्ट

सड़कें, स्मार्ट जलापूर्ति, छतों पर सौर प्रणाली जैसे क्षेत्रों पर भी काम चल रहा है।

श्री पुरी ने यह जानकारी 1 जनवरी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की एक बैठक को संबोधित करते हुए दी। इस बैठक में संसद सदस्य श्री राघव लखनपाल, श्री संतोख सिंह चौधरी, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और डॉ. सत्यनारायण जाटिया, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव आवास और शहरी मामले मंत्रालय और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

साथ ही श्री पुरी ने यह भी कहा कि स्मार्ट शहर परियोजना के तहत 90 शहरों ने कुल 1,91,155 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। विशेष क्षेत्र की परियोजनाओं में तेजी लाने की अनुमानित लागत 1,52,500 करोड़ रुपए होगी। 36,655 करोड़ के शेष निवेश को प्राप्त करने के लिए सभी शहरों में विशेष पहल की जा रही है। क्षेत्रवार परियोजनाएं और शहरी परियोजनाओं के अन्य व्यय के लिए अलग से 1998.49 करोड़ का कोष तैयार किया गया है। यह धन मिशन से जुड़े अन्य खर्चों में प्रयोग होगा। स्मार्ट शहर मिशन का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक लिमिटेड कंपनी के रूप में शहरी स्तर पर स्थापित विशेष उद्देश्य वाहक (एसपीवी) द्वारा किया जाता है और इसमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) की संयुक्त रूप से बराबर हिस्सेदारी होती है। ■

बुनियादी क्षेत्र की विकास दर 13 माह के उच्च स्तर पर

रिफाइनरी, स्टील और सीमेंट क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन से नवंबर में आठ प्रमुख उद्योगों ने जोरदार 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। पिछले साल नवंबर में इन उद्योगों की वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत और इस साल अक्टूबर में पांच प्रतिशत रही थी। बुनियादी क्षेत्र की वृद्धि दर 13 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। दरअसल, आठ प्रमुख उद्योगों में तेजी लौटना काफी हद तक सकारात्मक है, क्योंकि समग्र अर्थव्यवस्था पर इनका प्रभाव पड़ता है। स्टील और सीमेंट उत्पादन का अच्छा प्रदर्शन उल्लेखनीय है।

गौरतलब है कि ढांचागत क्षेत्र के आठ प्रमुख उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली हैं। औद्योगिक उत्पादन का बैरोमीटर माने जाने वाले आइआइपी में इन आठ उद्योगों का 40.27 प्रतिशत योगदान है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार नवंबर में रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि दर सालाना आधार पर क्रमशः 8.2 प्रतिशत, 16.6 प्रतिशत तथा 17.3 प्रतिशत रही। इसके साथ ही कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी।

रिफाइनरी उत्पादन का ईसीआई सूचकांक में 28.03 फीसदी भार है। इसमें साल 2017 के नवंबर में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 8.2 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। विद्युत उत्पादन जिसका ईसीआई सूचकांक में 19.85 फीसदी भार है, समीक्षाधीन अवधि में 1.9 फीसदी की तेजी दर्ज की गई।

स्टील उत्पादन का ईसीआई सूचकांक में 17.92 फीसदी योगदान है। इसमें समीक्षाधीन माह में 16.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। कच्चे तेल की निकासी जिसका 5.37 फीसदी है, उसमें नवंबर में 17.3 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। प्राकृतिक गैसों का उपसूचकांक जिसका 6.88 फीसदी भार है, उसमें इस अवधि में 2.4 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। ■

2016-17 में 16.37 करोड़ टन दूध का उत्पादन

भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना हुआ है। इस उपलब्धि का श्रेय दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई अनेक योजनाओं को जाता है। जहां 1960 के दशक में करीब 17-22 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, वह बढ़कर वर्ष 2016-17 में 16.37 करोड़ टन हो गया। विशेषकर 2013-14 की तुलना में 2016-17 की अवधि में 19% की वृद्धि हुई है। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने यह बात 28 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित डेयरी विकास पर परामर्श हेतु गठित समिति की बैठक में कही। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत विश्व में उस पटल पर पहुंच गया है, जहां दुग्ध व्यवसाय में वैश्विक स्तर पर उद्यमियों के लिए अनेक संभावनाएं उभर कर सामने आ रही है।

उन्होंने कहा कि इसी तरह प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2013-14 में 307 ग्राम से बढकर वर्ष 2016-17 में 351 ग्राम हो गई है, जो 14.3% की वृद्धि है। इसी प्रकार 2011-14 की तुलना में 2014-17 में डेयरी किसानों की आय में 23.77 % प्रतिशत की वृद्धि हुई। गत 3 वर्षों में प्रति वर्ष 5.53% की दर से दूध उत्पादन बढ़कर विश्व में दुग्ध उत्पादन की वार्षिक दर से आगे निकल गया है, जहां दुग्ध विकास की दर 2.09% रही है।

श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर विशेषकर भूमिहीन एवं सीमांत किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय उनके जीवन-यापन एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का जरिया बन गया है। करीब 7 करोड़ ऐसे ग्रामीण किसान परिवार डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनके पास कुल गायों की 80% आबादी है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की रुचि धीरे-धीरे अधिक प्रोटीन वाले उत्पादों की ओर बढ रही है एवं वेल्यु एडेड (मूल्य वृद्धि) उत्पादों का चलन भी बढ़ने के कारण दूध की मांग तेजी से बढ़ रही है। गत 15 वर्षों में दुग्ध सहकारी संस्थाओं ने अपने कुल उपार्जित दूध के 20% हिस्से को वेल्यु एडेड (मूल्य वृद्धि) दुग्ध पदार्थों मे परिवर्तित किया है, जिससे तरल दूध की अपेक्षा 20% अधिक आय प्राप्त होती है। श्री सिंह ने बताया कि ऐसी अपेक्षा है कि वर्ष 2021-22 तक 30% दूध को मूल्य वृद्धि पदार्थों मे परिवर्तित किया जाएगा।

श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ (वर्ष 2022) तक किसानों की आय को दोगुना करने हेतु किए गए संकल्प के आधार पर डेयरी किसानों की आय को भी दोगुना करने हेतु विभाग द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इस दिशा में डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के दो आधार रखे गए है: एक– हमारे दुधारु पशुओं की उत्पादकता बढाकर दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी कर

आय में वृद्धि कराना एवं दूसरा डेयरी किसानों को दी जाने वाली प्रति किलो दूध की मूल कीमत में वृद्धि करवाना।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हमारी कार्यप्रणाली को धीरे-धीरे आधुनिक तकनीक वाले वातावरण में बदला जाए।

श्री सिंह ने कहा कि डेयरी विकास हेतु 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- राष्ट्रीय डेयरी परियोजना-1 (एनडीपी 1), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) तथा डेयरी उदयमिता विकास योजना।

राष्ट्रीय डेयरी योजना–1:

इस योजना का कार्यान्वयन एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य की सहकारी दुग्ध संगठनों/ दुग्ध फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी):

इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य की सहकारी दुग्ध संगठनों/दुग्ध फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है।

डेयरी उद्यमिता विकास योजना:

इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्राम विकास बैंक) द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से जिले में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा किया जा रहा है।

डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि:

दुग्ध किसान की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से तथा श्वेत क्रांति के पूर्व प्रयासों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना वर्ष 2017-18 से प्रारंभ की गयी है। इस योजना का कार्यान्वयन एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य की सहकारी दुग्ध संगठनों/दुग्ध फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है। ■

हमें पुरुषार्थ करना होगा

| दीनदयाल उपाध्याय |

प्रत्येक व्यक्ति सुख की कामना लेकर कार्य करता है- भौतिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। सामूहिक और व्यक्तिगत रीति से विचार करते हुए चार पुरुषार्थ सामने आते हैं। इन पुरुषार्थो की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। हम सभी एक-दूसरे पर निर्भर हैं। हम परस्परावलंबी हैं। व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि तथा परमेष्टि, हम इस परस्परानुकूलता तक पहुंचे। इसके लिए कर्म का सिद्धांत और यज्ञ तक की कल्पना करनी पड़ेगी। समाज का कौन सा ढांचा होना चाहिए जिसमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाएं। पश्चिम ने इस बाह्य रचना पर बहुत जोर दिया है। केवल रचना-मात्र से ही जो प्राप्त करना चाहते हैं, वह नहीं हो सकता।

दो चीज़ें होती हैं-रूप और तत्त्व। तत्त्व के बिना रूप का कोई अर्थ नहीं है। किंतु पश्चिम में रूप पर ध्यान दिया जाता है। उसके लिए संस्था प्रजातंत्र या राजतंत्र चाहिए फिर संसदीय लोकतंत्र चाहिए। हमारे यहां बाह्य स्वरूप पर इतना जोर नहीं दिया जाता। हम समाज के तत्त्व, स्वत्व और बलशाली होने पर जोर देते हैं, क्योंकि केवल रचना करने से तो काम नहीं चलेगा। चाबी के बिना घड़ी कैसे चलेगी? चाबी तो उसमें भी हाथ से भरनी पड़ती है। बिना हिले-डुले काम नहीं चल सकता। मान लो कि बिना हिले-डुले कोई ऐसा यंत्र बन जाए, जिसमें कुछ श्रम न करना पड़े... समाज

हमें जो कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए साधन रूप में चार बातों की आवश्यकता होती है-शिक्षा, स्वतंत्रता, शांति और पौरुष। इसके लिए चार प्रकार के साधन हैं-पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहिए मोक्ष चाहिए अर्थ चाहिए और शिक्षा चाहिए, लेकिन शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी ही नहीं। यह तो छोटा सा अंग है। उन सारी बातों पर विचार करना होगा, जिनसे हम अपने ध्येय की प्राप्ति कर सकते हैं।

की भी रचना स्वयं ही चलती रहे, कुछ न करना पड़े। किसी ने कहा कि सारी व्यवस्था यदि अच्छी है तो फिर विकार क्यों आया? वास्तविकता यह है कि व्यवस्थाएं तो शक्ति के आधार पर ही

चलती हैं। कुशल कारीगर को हथियार तो चाहिए ही, तभी वह अपनी कारीगरी दिखा सकता है। पेड़ काटने के लिए यदि आप कुल्हाड़ी-आरी देते हैं, तभी पेड़ कटेगा। थर्मामीटर से तो पेड़ नहीं कटता। दूसरी ओर, यदि मज़बूत कुल्हाड़ी रख दिया, काटने वाले के हाथ में शक्ति ही नहीं है, तब पेड़ कैसे कटेगा? वह तो अपना पैर ही काट लेगा, किंतु दूसरी बात का भी विचार किया जाना चाहिए कि कौन चलाने वाला है। हमें जो कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए साधन रूप में चार बातों की आवश्यकता होती है-शिक्षा, स्वतंत्रता, शांति और पौरुष। इसके लिए चार प्रकार के साधन हैं-पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहिए मोक्ष चाहिए अर्थ चाहिए और शिक्षा चाहिए, लेकिन शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी ही नहीं। यह तो छोटा सा अंग है। उन सारी बातों पर विचार करना होगा, जिनसे हम अपने ध्येय की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें पुरुषार्थ करना होगा। संस्कारों के द्वारा अध्यापन भी आवश्यक है, स्वाध्याय, चिंतन, मनन-इनके द्वारा अपने अंदर की शक्तियों को जाग्रत् करते हैं। लोकमत भी इसी दिशा में हो सकता है। शिक्षा हुई तब भी स्वतंत्रता की भूख तो मानवता को सदा से रही है। मानवता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता

ही सब कुछ नहीं है, परराज्य से छुटकारा मिलना ही स्वतंत्रता नहीं है। अपने लोगों के राज्य करते हुए भी हम यदि स्वत्व के आधार पर चलें, तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक-हर तरह की स्वतंत्रता चाहिए।

हम किसी देश की अर्थ नीति से न बंधे रहें, यह ठीक है। किंतु कुछ और बातें भी हैं-धन के अभाव में आर्थिक परतंत्रता हो जाती है। रोटी, शरीर की निपुणता के लिए जो-जो भौतिक सामर्थ्य चाहिए, साधन सामग्री उपलब्ध करने के लिए धन का अभाव नहीं रहना चाहिए। धन के अभाव में रोटी कमाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ब्राह्मण अपना धर्म-कर्म छोड़कर दूसरों के आगे हाथ फैलाए तो ठीक नहीं लगता, लेकिन धन मिल जाने पर भी आर्थिक परतंत्रता नहीं गई। इसका कारण है, धन के प्रति आसक्ति, कंजूस होना। कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, खाना नहीं खाता, पैसा जोड़कर रखता जाता है। वह साधन को साध्य मानकर चलता है। गाड़ी में से उतरकर तांगा, रिक्शा में न बैठकर पैदल ही चलने लगता है। रास्ते में प्यास लगती है तो भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता। जेब से रुपया निकालकर देखा और सोचने लगा, 'सोलह कला अवतार टूट जाएगा। चाहे मर जाऊं, पर तुझे न भुनाऊंगा।' कहकर अपने पास ही रख लिया। यह भी एक प्रकार की परतंत्रता है। वह परतंत्र है स्वतंत्र नहीं। जिसे पता ही नहीं कि कैसे खर्च करे, निमित्त भी पता नहीं, ऐसा व्यक्ति भी आर्थिक दृष्टि से परतंत्र कहा जाएगा।

आसक्ति ही नहीं तो विलास बुद्धि भी न हो, 'मेरी कमीजें बारह चाहिए जूते आठ', हॉस्टल के कमरे में जूतों का बाजार सा खुला था। भोग विलास की वृत्ति भी स्वतंत्र न होने देगी। तीसरी बात यदि यह पता ही नहीं कि इसे खर्च कैसे करें, निमित्त भी पता नहीं, ऐसा व्यक्ति भी परतंत्र कहलाता है। हजरत मूसा (यहूदियों के पैगंबर) पृथ्वी पर जब आए तो उन्होंने एक स्त्री को देखा। कुछ तन ढकने को नहीं था। उसने हजरत मूसा से कहा कि भगवान् से कहो कि कुछ ढ़कने को तो दे। इसी तरह एक अमीर आदमी मिला। उसने कहा कि भगवान् से पूछो कि इस धन को कैसे खर्च करूं। तो ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता। आलस्य, तामसिक भावना, भोग-विलास, अभाव और अंत में वही परतंत्रता। इसीलिए लोग आर्थिक दृष्टि से परतंत्र हो जाते हैं। राजा हर्ष अपने काल में पांच वर्ष तक कमाकर सब कुछ दान कर देता था। रघु ने भी सब बांट दिया। मिट्टी का बरतन ही बचाया। फिर कुबेर पर आक्रमण कर गुरु दक्षिणा दी। अतिरिक्त धन को अच्छे काम में लगाना चाहिए।

जहां लड़ाई, वहीं पर शांति हमारे यहां नहीं मानी गई। मन की शांति, समाज की शांति, सभी प्रकार की शांति मिलनी चाहिए-भौतिक, मानसिक, बौद्धिक। मृत्यु की शांति नहीं है, जहां सृष्टि की रचना हो और सभी व्यवस्था ठीक हो, ऐसी शांति चाहिए। भगवान् कृष्ण ने महाभारत का युद्ध भी शांति के लिए कराया। शांति आंतरिक तथा बाह्य जीवन की भी होनी चाहिए। साथ-साथ पौरुष भी तो चाहिए। इसमें पराक्रम, प्रयत्न, निष्ठा, विवेक होना चाहिए दुस्साहस पौरुष के अंतर्गत नहीं आता। जहां पर साधन होते हैं, वहीं पर व्यवस्था का प्रश्न आता है।

इन साधनों के साथ-साथ फिर हमारे चार आश्रम, चार वर्ण होते हैं। व्यक्ति की आश्रम की दृष्टि से व्यवस्था की जाती है। इन्हीं के द्वारा समाज के प्रति व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तभी परस्परानुकूलता आती है। वर्ण व्यवस्था में हरेक का विशिष्ट कार्य होता है। आजकल एक नारा है वर्ग विहीन समाज, जो गलत है। यह वहीं हो सकता है, जहां अराजकता का वातावरण हो। शिक्षार्थी और शिक्षक, परोसने वाले और भोजन करने वाले एक ही वर्ग नहीं है। वर्गों का विभाजन कार्यानुसार होता है। मार्क्स ने केवल पैसे के आधार पर विभाजन किया। हमने गरीब-अमीर नहीं तो, कर्तव्य के आधार पर वर्गीकरण किया। समाज में ज्ञान, शिक्षण,

जहां लड़ाई, वहीं पर शांति हमारे यहां नहीं मानी गई। मन की शांति, समाज की शाति, सभी प्रकार की शांति मिलनी चाहिए-भौतिक, मानसिक, बौद्धिक। मृत्यु की शांति नहीं है, जहां सृष्टि की रचना हो और सभी व्यवस्था ठीक हो, ऐसी शांति चाहिए। भगवान् कृष्ण ने महाभारत का युद्ध भी शांति के लिए कराया। शांति आंतरिक तथा बाह्य जीवन की भी होनी चाहिए। साथ-साथ पौरुष भी तो चाहिए।

रक्षा, अर्थ, सबकुछ प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। जिन साधनों के आधार पर सब बढ़ सकते हैं, वैसे लोग चाहिए। आप लोग तो रेलगाड़ी में आराम से बैठकर चले जाते हैं, लेकिन इंजन में किसी न किसी को काम करना पड़ता है। आप लोग तो आराम से रात को गाड़ी में सोते हुए जाते हैं, लेकिन कितने ही लोग जागते हैं रात भर स्टेशन और गाड़ी में। तब व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। एक-दूसरे के साथ वैज्ञानिक आधार पर, परस्परानुकूलता के आधार पर व्यवस्था करनी पड़ती है। कार्य के आधार पर व्यवस्था करनी पड़ती है। ये ही चार मोटे कार्य दुनिया के सभी देशों में किसी-न-किसी रूप में रहते हैं। इन चार संस्थाओं का हमारे यहां सूक्ष्म विवेचन किया गया है। समाज शास्त्र इन्हें पांच सस्थाओं में बांटता हैं- 1. परिवार 2. शिक्षा, 3. धर्म, 4. वाणिज्य, और 5. राज्य या राजनीतिक संस्थान। आज राज्य की सस्था को छोड़कर बाक़ी कोई बहुत संगठित नहीं है। ■ क्रमश...

(संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : दिल्ली, जून 14, 1958)

राजमाता विजया राजे सिंधिया

(12 अक्टूबर, 1919 – 25 जनवरी, 2001)

राजमाता विजया राजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 में सागर, मध्य प्रदेश के राणा परिवार में हुआ था। विजया राजे सिंधिया के पिता श्री महेन्द्रसिंह ठाकुर जालौन ज़िला के डिप्टी कलैक्टर थे और इनकी माता श्रीमती 'विंदेश्वरी देवी' थीं। विजया राजे सिंधिया का विवाह के पूर्व का नाम 'लेखा दिव्येश्वरी' था। विजया राजे सिंधिया के पुत्र माधवराव सिंधिया, पुत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया हैं।

विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के रूप में जाना जाता था। भारत के विशालतम और संपन्नतम राजे-रजवाड़ों में से ग्वालियर एक था। उस रियासत के महाराजा के साथ उनका विवाह हुआ था। 1957 में विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और वे विजयी हुईं। अपने पति की मृत्यु के बाद सन् 1962 में कांग्रेस के टिकट पर वे संसद सदस्य बनीं। पांच साल के बाद अपने सैद्धांतिक मूल्यों के कारण वे कांग्रेस छोड़कर जनसंघ में शामिल हो गईं। एक राज परिवार से रहते हुए भी वे अपनी ईमानदारी, सादगी और प्रतिबद्धता के कारण पार्टी में सर्वप्रिय बन गईं। शीघ्र ही वे पार्टी में शक्ति स्तंभ के रूप में सामने आईं।

राजमाता विजया राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थीं। राजमाता को जनसंघ और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं जैसे – अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ काम किया। यही नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1967 में मध्य प्रदेश में सरकार गठन में उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विजया राजे सिंधिया का सार्वजनिक जीवन प्रभावशाली और आकर्षक था, हालांकि व्यक्तिगत जीवन में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

सन 1989 के आम चुनाव में विजया राजे सिंधिया एक बार फिर गुना से भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कीं। इससे पहले 22 साल पूर्व सन् 1967 में राजमाता वहां से जीती थीं। 1991 के चुनाव में पुनः

राजमाता विजया राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थीं। राजमाता को जनसंघ और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं जैसे – अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ काम किया। यही नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1967 में मध्य प्रदेश में सरकार गठन में उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित किया।

राजमाता ने आम आदमी की तरह जीवन जिया

राजमाता सिंधिया सिद्धांतों के प्रति समर्पित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत विदुषी जननायक थीं। उन्होंने महलों के वैभव को छोड़कर जनता के न्याय के लिए संघर्ष का मार्ग स्वीकार किया और सड़कों पर उतरकर राजमाता से लोकमाता बन गईं।

राजमाता ने जीवन पर्यन्त आम आदमी की तरह जीवन जिया, सेवा की उनमें ललक थी। सादगी और सरलता उनका स्वभाव था। राजमाता का मानना था कि अपनों की जड़ खोदकर कभी कोई दूसरों का चहेता नहीं बना है।

राजमाता सिंधिया लंबे समय तक महिलाओं से जुड़ी रहीं और उन्हें सदैव प्रेरित करती थीं। वे हमेशा सेवा के लिए समर्पित रहीं। उन्हें पद और सत्ता ने कभी आकर्षित नहीं किया। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया।

राजमाता त्याग एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने लोगों के दिलों पर बरसों राज किया। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने जनसेवा से कभी अपना मुख नहीं मोड़ा। राजमाता का सपना था की जब देश में कमल खिलेगा तभी अंतिम सांस लेंगी। ये स्वप्न पूरा हुआ और उनके जीवित रहते ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। सन् 1998 से राजमाता का स्वास्थ्य ख़राब रहने लगा और 25 जनवरी, 2001 में राजमाता विजया राजे सिंधिया का निधन हो गया। ■

चुनावी बॉन्ड क्यों ज़रूरी?

अरूण जेटली

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हालांकि पिछले सात दशकों में कई क्षेत्रों को मजबूत किया गया, लेकिन भारत कभी भी पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग प्रणाली विकसित करने में सक्षम नहीं हो पाया। चुनाव और राजनैतिक दल संसदीय लोकतंत्र की मौलिक विशेषताएं हैं। चुनावों में पैसा लगता है। राजनैतिक दलों के साल भर के कामकाजों में काफी व्यय शामिल होता है। पार्टियां देश भर में अपने कार्यालय चलाती हैं। स्टाफ का वेतन, यात्रा व्यय, स्थापना व्यय आदि राजनैतिक पार्टियों के नियमित खर्चे हैं। ऐसा कोई साल नहीं होता जिसमें कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव न होता हो। उम्मीदवारों के निजी खर्च के अलावा राजनैतिक दलों को भी चुनाव प्रचार, यात्रा और चुनाव सम्बंधी अन्य व्यय करने पड़ते हैं। ये खर्चे सैंकड़ों करोड़ तक पहुंच जाते हैं। इसके बावजूद राजनैतिक प्रणाली के लिए कोई पारदर्शी फंडिंग प्रक्रिया नहीं है।

राजनैतिक फंडिंग की परम्परागत प्रणाली दान पर आश्रित है। ये सभी छोटे-बड़े दान अलग-अलग स्रोतों, जैसे - राजनैतिक कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों, छोटे व्यापारियों और यहां तक कि बड़े उद्योगपतियों आदि से आते हैं। राजनैतिक व्यवस्था के वित्तपोषण का पारंपरिक तरीका है - नकद में दान लेना और नकद में ही व्यय करना। दान के स्रोत अज्ञात या छद्म होते हैं। रकम का खुलासा कभी नहीं किया जाता था। वर्तमान प्रणाली अज्ञात स्रोतों से काला धन आना सुनिश्चित करती है। यह पूर्ण रूप से एक अपारदर्शी प्रणाली है। ज्यादातर राजनैतिक समूह इस प्रणाली

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली पहली एनडीए सरकार के दौरान एक बड़ा कदम उठाया गया। आयकर अधिनियम को संशोधित किया गया, ताकि उसमें यह प्रावधान जोड़ा जा सके कि राजनैतिक दलों को दिया गया दान खर्च के रूप में माना जाएगा और दानदाता को कर में छूट का लाभ मिलेगा। यदि राजनैतिक पार्टी निर्धारित तरीके से अपने दान का ब्यौरा देगी, तो उसे भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।

से संतुष्ट लगते हैं और यदि यह आगे भी जारी रहे तो उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए एक वैकल्पिक व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया जा रहा है जो राजनैतिक फंडिंग प्रणाली को स्वच्छ करने के लिए तैयार हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली पहली एनडीए सरकार के दौरान एक बड़ा कदम उठाया गया था। आयकर अधिनियम को संशोधित किया गया, ताकि उसमें यह प्रावधान जोड़ा जा सके कि राजनैतिक दलों को दिया गया दान खर्च के रूप में माना जाएगा और दानदाता को कर में छूट का लाभ मिलेगा। यदि राजनैतिक पार्टी निर्धारित तरीके से अपने दान का ब्यौरा देगी, तो उसे भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। राजनैकि दलों को आयकर प्राधिकरणों और चुनाव आयोग दोनों में अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना था। उम्मीद थी कि दानदाता अब चेक के माध्यम से ज्यादातर दान देने लगेंगे। कुछ दानदाताओं ने इसे अपनाना भी शुरू कर दिया था लेकिन अधिकांश दानदाता राजनैतिक दलों को दिए गए अपने दान की रकम का खुलासा करने के इच्छुक नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें विपक्षी पार्टियों से मिलने वाले नकारात्मक परिणामों की चिंता थी। "पास थ्रू" चुनावी ट्रस्ट उपलब्ध कराने के लिए यूपीए सरकार के दौरान यह कानून फिर से संशोधित किया, ताकि दानकर्ता अपने पैसे चुनावी ट्रस्ट में डाल सके जो उसे विभिन्न राजनैतिक दलों में बांट दे। इन दोनों सुधारों के परिणामस्वरूप दान का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही चेक के रूप में प्राप्त होना शुरू हो पाया।

इस सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करने के क्रम में, 2017-18 के अपने बजट भाषण में मैंने घोषणा की थी कि मौजूदा व्यवस्था काफी हद तक विस्तारित हो जाएगी और कई मायनों में राजनीतिक दलों को शुद्ध धन दान किया जा सकेगा। चैक द्वारा राजनैतिक चंदा देने के एवज् में दानकर्ता टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं और साथ ही दानकर्ता ऑनलाइन माध्यमों द्वारा राजनैतिक दलों को चंदा

दे सकते हैं। नकद के रूप में राजनैतिक दलों को दिये जाने वाले चंदे की अधिकतम निर्धारित सीमा 2000/- रुपये है साथ ही हमने चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा की थी। यह योजना राजनैतिक चंदे में सफेद धन के परिचालन के साथ सक्षम रूप से पारदर्शिता का निर्वाह करते हुए राजनैतिक दलों का वित्त पोषण सुनिश्चित करेगी। मैं मानता हूं कि राजनैतिक दलों को दान देने के लिए ऑनलाइन माध्यम और चैक बेहतरीन और आदर्श तरीके हैं, पर दान देने के ये प्रणालियां अभी भारतीय परिप्रेक्ष्य में उतनी चलन में नहीं हैं, क्योंकि इनसे दानकर्ता की पहचान सार्वजनिक हो जाती है।

हालांकि, चुनावी बॉन्ड योजना जिसे कुछ दिन पहले मैंने संसद के पटल पर रखा था, में कुल साफ धन और राजनैतिक धन व्यवस्था की प्रणाली में आने वाली पर्याप्त पारदर्शिता की संभावना है। एक दाता किसी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा केवल एक निर्दिष्ट बैंक से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। हमारी इस परिकल्पना से राजनैतिक दलों को सफेद धन मिलेगा, इसके कारण राजनैतिक व्यवस्था में पारदर्शिता का पर्याप्त समावेश रहेगा। दानकर्ता चुनावी बॉन्ड निर्धारित बैंको की किसी भी शाखा से खरीद सकते हैं। दानकर्ताओं को अपने खाते में उस राशि का खुलासा करना होगा जो उसने खरीदी है। बॉण्ड़ जारी होने के बाद पन्द्रह दिनों तक वैध रहेगा। बॉण्ड़ का इस्तेमाल केवल राजनीतिक दलों के पूर्व निर्धारित खाते में धन देने के लिए किया जा सकता है। सभी राजनैतिक दलों को चुनाव आयोग के समक्ष टैक्स रिटर्न में चुनावी बॉण्ड़ के माध्यम से मिलने वाले चंदे का खुलासा करना होगा।

सभी तरह के लेन-देन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किये जायेंगे। वर्तमान परिदृश्य में राजनैतिक चंदा लेने वाले दलों और देने वाले लोगों के मध्य पारदर्शिता का बेहद अभाव है। इसी के तहत सियासी पार्टियों की दान की राशि और व्ययों का लेखा-जोखा सभी अज्ञात है। पारदर्शिता के कुछ तत्व तब अस्तित्व में आएंगे जब दानदाता उस राशि की घोषणा करेंगे, जो उन्होनें बॉण्ड़ के माध्यम से सियासी चंदे के रूप में दी है और सियासी पार्टियां ये स्वीकार करेंगी कि उन्हें किस-किस से और कितना राजनैतिक चंदा मिला है। किसी दानकर्ता ने एक राजनैतिक पार्टी को कितना दान दिया है, यह केवल उस दानकर्ता को ही पता होगा। यह आवश्यक है क्योंकि पिछले अनुभवों से पता चलता है कि एक बार यह घोषित हो गया और दानकर्ताओं को यह योजना आकर्षक नहीं लगी तो वह फिर से नकद में दान देने के अवांछनीय विकल्प पर वापस चले जाएंगे।

एक तरफ नकद दान की मौजूदा प्रणाली है, जिसमें पूरी तरह से अशुद्ध पैसा शामिल है और जो अपारदर्शी है। दूसरी तरफ नई योजना है जो दानकर्ता को चेक, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन या चुनावी बॉन्ड के द्वारा पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से दान करने का विकल्प देती है। वास्तव में अब इन दोनों के बीच सावधानीपूर्वक चुनाव करना होगा। चेक, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन और चुनावी बॉन्ड, जहां इन तीनों ही तरीकों में साफ धन शामिल है और पहले दोनों तरीके पूर्ण रूप से पारदर्शी हैं, वहीं चुनावी बॉन्ड योजना मौजूदा गैर-पारदर्शी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

भारत में राजनैतिक वित्तपोषण की प्रणाली को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया को और मजबूती देने के लिए सरकार सभी सुझावों पर विचार करना चाहती है। यह भी दिमाग में रखना होगा कि अव्यावहारिक सुझाव नकदी आधारित व्यवस्था को नहीं सुधार सकते, बल्कि वह केवल इसे मजबूत ही करेंगे। ■

(लेखक केंद्रीय वितमंत्री हैं)

विदेशी मुद्रा भंडार 409 अरब डालर के नये रिकॉर्ड स्तर पर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 29 दिसंबर को 4.444 अरब डॉलर बढ़कर 409.366 अरब डॉलर की सर्वकालिक रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि विदेशी मुद्रा आस्तियों में भारी तेजी के कारण यह तेजी आई है। यह कुल विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। विदेशी मुद्रा भंडार पिछले वर्ष आठ सितंबर को पहली बार 400 अरब डॉलर के स्तर को लांघ गया था, लेकिन उसके बाद में उसमें घट-बढ़ होती रही। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तिया 4.423 अरब डॉलर बढ़कर 385.103 अरब डॉलर का हो गईं।

अमरीकी डॉलर में अभिव्यक्त किए जाने वाले एफसीए में मुद्राभंडार में रखे गए यूरो, पौंड और जापानी येन जैसे गैर-अमरीकी मुद्राओं की तेजी/अवमूल्यन के प्रभावों को शामिल किया जाता है। स्वर्ण आरक्षित भंडार 20.716 अरब डॉलर पर अपरिवर्तित बना रहा। रिजर्व बैंक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) में विशेष निकासी

अधिकार 89 लाख डॉलर बढ़कर 1.511 अरब डॉलर हो गया। इसने कहा कि आई.एम.एफ. में देश का मुद्रा भंडार भी 1.21 करोड़ डॉलर बढ़कर 2.035 अरब डॉलर हो गया। ■

तीन तलाक पर कांग्रेस का धोखा

| कैलाश विजयवर्गीय |

आखिरकार कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों का मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलाने के नाटक का राज्यसभा में पर्दाफाश हो गया। यह भी साफ हो गया कि 1400 साल से मुस्लिम महिलाओं को जहन्नुम में धकेलने वाली कुप्रथा को कांग्रेस खत्म करने के पक्ष में नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस ने तीन तलाक कानून का समर्थन किया और तृणमूल कांग्रेस ने चर्चा में हिस्सा लेने के लिए नोटिस तक नहीं दिया था, अब यही दल राज्यसभा में कानून न बने, इसके लिए अलोकतांत्रिक तरीके अपना रही है। राज्यसभा में बिल को प्रवर समिति को भेजने और समिति के सदस्यों के नाम तय करने के लिए सदन के नियमों तक का पालन नहीं किया। कांग्रेस के रुख के कारण मुस्लिम महिलाओं में भारी नाराजगी है। मुस्लिम महिलाओं को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संसद में कानून बनेगा और उन्हें शान से जीने का हक मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को यह भी उम्मीद थी कि संसद से कानून बनने के बाद उन्हें समाज में जारी अन्य कुप्रथाओं से मुक्ति मिलेगी। मुस्लिम महिलाओं को आखिर कांग्रेस और दूसरे दल क्यों बराबरी का हक नहीं दिलाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि इससे मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रही है। ऐसा कहकर कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त को दिए गए फैसले का निरादर कर रहे हैं। 1400 साल पुरानी तीन तलाक की

कुप्रथा पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने बहुमत से फैसला दिया था कि तलाक-ए-बिद्दत वॉइड, असंवैधानिक और गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को छह महीने में कानून बनाने को कहा था। पहले केंद्र की तरफ से यह कहा गया था कि कानून बनाने की जरूरत है पर मुस्लिम समाज में लगातार जारी तीन तलाक की खबरों के बाद कानून बनाने की जरूरत महसूस की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह लगा कि मुस्लिम समाज में वॉट्सएप, ईमेल, एसएमएस, फोन, चिट्ठी जैसे अजीब तरीकों से तलाक देने पर रोक लगेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या मुस्लिम परम्पराओं में इन सब तरीकों के जरिये तलाक देने का रिवाज था। मुस्लिम समाज की महिलाएं चाहती हैं कि कानून के अनुसार तलाक की व्यवस्था हो। इसके लिए वे लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं।

मीडिया में बार-बार खबरें आ रही कि किस तरह मुस्लिम महिलाओं को छोटी-छोटी बातों पर तीन तलाक देकर उनकी जिंदगी को तबाह किया जा रहा है। कोई महिला देर से उठे और उसका शौहर उसे केवल तीन तलाक कह कर घर से निकाल दें, यह कैसा रिवाज है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कानून बनाने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया और वहां से पारित भी हो गया।

हम सब जानते हैं कि मीडिया में बार-बार खबरें आ रही कि किस तरह मुस्लिम महिलाओं को छोटी-छोटी बातों पर तीन तलाक देकर उनकी जिंदगी को तबाह किया जा रहा है। कोई महिला देर से उठे और उसका शौहर उसे केवल तीन तलाक कह कर घर से निकाल दें, यह कैसा रिवाज है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कानून बनाने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया और वहां से पारित भी हो गया। कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो बहुत वाहवाही लूटी थी और कहा था कि हमारे कारण सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है, पर अब कांग्रेस राज्यसभा में बिल पारित कराने से क्यों पीछे भागे रही है। यह कांग्रेस की राजनीति का एक और दोहरा रवैया उजागर हुआ है। कांग्रेस की ढोंगी राजनीति का सच जनता के सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री तो खुद नमाज पढ़ती हैं, अब खुलकर तीन तलाक कानून के खिलाफ सामने आ गई हैं। कांग्रेस और दूसरे दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल नहीं होना देना चाहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अपने को

सेक्युलर कहने वाले कम्युनिस्ट भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अगस्त में खुशी जाहिर करने वाले कांग्रेस के नेता राज्यसभा में बिल का विरोध कर राजनीति करने में लगे हैं। मुस्लिम महिलाओं को लग रहा है कि जिस तरह से राजीव गांधी के जमाने में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें इंसाफ नहीं मिला था, आज भी उसी तरह का धोखा कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है।

कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि राजनीति में घटते असर के कारण इस तरह का नाटक जरूरी है। मुस्लिम समाज भी यह अच्छी तरह समझता है कि कांग्रेस के नेता केवल राजनीति फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते रहे हैं। यह सब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को मुस्लिम समाज का समर्थन नहीं मिला। इतना ही विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिमों को चुनाव में उतारने वाली बहुजन समाज पार्टी को भी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने कोई तरजीह नहीं दी। मीडिया में आई खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा के उम्मीदवारों का समर्थन दिया था, इस कारण भी कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों को शायद डर लग रहा है कि संसद में तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं का झुकाव भाजपा की तरफ होगा। यह डर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लग रहा है। इतना तो साफ हो गया है कि राजनीतिक फायदे के लिए जो नाटक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करती थी, उसी तरह का नाटक राजीव गांधी करते रहे, वही राजनीति सोनिया गांधी करती रही और उसी रास्ते पर राहुल गांधी चल रहे हैं। इससे देश का तो कोई भला नहीं होगा। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा राजनीतिक फायदे के लिए तीन तलाके के लिए कानून बना रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक जो भी फैसले किए हैं, देश के विकास के लिए किए हैं। मोदी सरकार की मंशा केवल मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब हिन्दू कोड बिल आया तो उस समय विरोध किया गया था। आखिर में हिन्दू कोड बिल बना और अब तीन तलाक के खिलाफ कानून तो बनेगा, कुछ समय बेशक लग सकता है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि राजनीति में घटते असर के कारण इस तरह का नाटक जरूरी है। मुस्लिम समाज भी यह अच्छी तरह समझता है कि कांग्रेस के नेता केवल राजनीति फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते रहे हैं। यह सब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को मुस्लिम समाज का समर्थन नहीं मिला।

ग्रामीण, कृषि क्षेत्र में सरकार 2,90,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है : अरुण जेटली

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 5 जनवरी को कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है तथा इन पर 2,90,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रेम सिंह चंदूमाजरा, दिवाकर रेड्डी, गोपाल रेड्डी और मोहम्मद सलीम के प्रश्नों के उत्तर में श्री जेटली ने कहा कि कृषि क्षेत्र को सहयोग की जरूरत पड़ती है। सरकार ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र पर 2,90,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

किसानों की मदद से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें किसानों की मदद के लिए प्रस्ताव भेजती हैं और केंद्र उन पर विचार करता है और फिर एक निश्चित अनुपात में मदद दी जाती है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष में उर्वरक पर 70,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है, ताकि किसानों को अधिक से अधिक राहत मिल सके। ■

मातृ शक्ति को सलाम

प्रशांत मिश्र

एक साथ तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) के खिलाफ सरकार के प्रयास का समर्थन देश और राजनीतिक दलों का बड़ा हिस्सा कर रहा है। यह सवाल जरूर है कि कितने खुले दिल से कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो मजबूर होकर साथ खड़े दिख रहे हैं। मुस्लिम समाज में भी एक गुट ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार की कानूनी कार्रवाई को समाज को बांटने वाली कवायद के रूप में देख रहा है। जो कट्टर हैं वे अपना प्रभुत्व बरकरार रखने के लिए ऐसा ही करेंगे, लेकिन उन्हें परोक्ष रूप से समर्थन देने वालों को जरूर अपना नजरिया बदलना चाहिए। देश उनसे भी जवाब मांगेगा। उन्हें यह देखना चाहिए कि नारी समाज के लिए अगर हर क्षेत्र में समानता और सुरक्षा का दायरा बढ़ा है, तो मुस्लिम महिलाओं को अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है? तीन तलाक के खिलाफ कानून और महरम के बिना हज जैसा फैसला समाज का विभाजन नहीं, बल्कि एकजुट करने का प्रयास है। सरकार का फर्ज है कि जाति,धर्म और संप्रदाय में किसी भेदभाव के बिना 'आधी आबादी' को पूरा अधिकार और सम्मान मिले। मोदी सरकार की सोच के केंद्र में समाज और महिला रही है। महिलाओं की सुरक्षा, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कदम, आर्थिक सशक्तिकरण,न्याय आदि पर तीन चार वर्षों में सार्थक पहल दिखी है।

वे लोग जो मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण को समाज में विभाजन के रूप मे देख रहे है उन्हें जवाब देना होगा कि विकास की मुख्यधारा में तेज गति से बढ़ने का अधिकार क्या केवल हिंदू महिलाओं को है? अगर मुस्लिम महिलाओं को अवसर मुहैया कराया जाए तो क्या यह नकारात्मक राजनीति है? अगर कोई ऐसा सोचता है तो हम आशा ही कर सकते हैं कि नए साल में उनकी सोच में कुछ सकारात्मक बदलाव आए। वे व्यक्तिगत राजनीति और प्रभुत्व को छोड़कर उस समाज और देश के बारे में सोचें, जो संकुचित मानसिकता के कारण ही क्षमता के बावजूद विकसित देशों के साथ दौड़ लगाने में असफल रहा है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजना पुरुष महिला अनुपात को दुरुस्त करने के लिहाज से शुरू की गई थी। यह किसी जाति धर्म के खांचे से बाहर है। असुरक्षा महिलाओं के बढ़ते कदम को रोकती है। हर राज्य में महिला हेल्प लाइन और वन स्टाप सेंटर स्थापित किए गए। इसका मकसद है कि किसी भी आपात स्थिति में फिर वह चाहे मेडिकल मदद की बात हो या पुलिस की, महिलाओं के साथ खड़ा होना। इसमें हिंसा की शिकार महिलाओं को मानसिक काउंसलिंग और अस्थाई शेल्टर मुहैया कराने की भी व्यवस्था है। एसिड अटैक पीड़िता को दिव्यांगों को मिलने वाले अधिकार देने की बात हुई। राज्यों को यह अधिकार भी दिया गया कि वे इससे परे भी पीड़िता को पांच लाख रुपये तक की आर्थिक मदद और इलाज मुहैया करा सकते हैं। निर्भया फंड में पहली बार 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। 2019 तक एक ऐसा इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार हो जाएगा, जिससे देश के नौ सौ रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी के जरिये नजर रहेगी। इससे महिलाओं और बच्चियों की तस्करी पर अंकुश लगेगा। पुलिस की कमी और आबादी के अनुपात में पुलिसकर्मियों की संख्या वैसे ही चिंताजनक है। ऐसे में महिला पुलिस की मौजूदगी पर तो सवाल पूछना भी लाजिमी नहीं होता, लेकिन यह सुखद है कि अब तक आठ राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों ने पुलिस में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। कोशिश है कि पूरे देश में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़े। एक रोचक तथ्य है कि 'जेंडर चैंपियन' नाम का एक कार्यक्रम देश के सौ विश्वविद्यालयों और लगभग डेढ़ सौ कालेजों मे चल रहा है। इसके जरिये युवाओं को संवेदनशील बनाया जा रहा है, ताकि युवतियों और महिलाओं के अधिकार और महत्व को समझा जा सके। कामगार महिलाओं के लिए मातृत्व विधेयक में संशोधन बड़ी राहत लेकर आया है। उनका मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। उनके लिए क्रैच की भी व्यवस्था की गई है। ध्यान रहे कि ऐसी महिलाओं की बड़ी संख्या थी जो मातृत्व के बाद अपनी नौकरी खो देती थीं। उन्हें नया अवसर मिला है। ऐसी महिलाओं की कमी नहीं जो असंगठित क्षेत्र में नौकरी करती हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई, जो पहले बच्चे के जन्म के लिए मातृत्व लाभ देती है। माना जाता है कि खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं उसी वक्त शोषण का शिकार बनाई जाती हैं, जब वे रात के अंधेरे में शौचालय जाती हैं। ऐसे में स्वच्छता अभियान केवल सफाई से ही नहीं महिला सुरक्षा से भी जुड़ता है। आंकड़े बताते है कि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 39 फीसद से बढ़कर 71 फीसद हो गया है। उज्ज्वला योजना तो जैसे

सरकार का फर्ज है कि जाति, धर्म और संप्रदाय में किसी भेदभाव के बिना 'आधी आबादी' को पूरा अधिकार और सम्मान मिले। मोदी सरकार की सोच के केंद्र में समाज और महिला रही है। महिलाओं की सुरक्षा, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कदम, आर्थिक सशक्तीकरण, न्याय आदि पर तीन चार वर्षों में सार्थक पहल दिखी है।

गरीब महिलाओं की आंखों की रोशनी बनकर आई। अब तक सवा तीन करोड़ गरीब घरों को एलपीजी कनेक्शन और गैस का चूल्हा उपलब्ध कराया गया है, ताकि वे धुएं से दूर रहें। इन सभी योजनाओं में ऐसी कोई भी नहीं जो जाति या धर्म के आधार पर हो। हां, गरीब और बेसहारा औरतों को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर हुई है। फिर मुस्लिम महिलाओं को दूसरी महिलाओं की तरह ही अधिकार देने पर शोर शराबा कैसा? राजनीति समाज को बांटकर नहीं, बल्कि जोड़कर चलती है। जो समाज को जितना ज्यादा जोड़ेगा, उसका आधार उतना बड़ा होगा। सरकार का जिम्मा बनता है कि वह कमजोरों को सबसे पहले उठाकर खड़ा करे। इसी क्रम में अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अत्याचार के कानून में संशोधन भी किया गया। वहीं ओबीसी के वर्गीकरण के लिए आयोग बनाया गया है। यह किसी से छिपा नहीं कि क्रीमी लेयर प्रावधान के बावजूद ओबीसी समाज के ऐसे लोग आरक्षण की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाते थे जो सचमुच पिछड़े हैं। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की तर्ज पर ही ओबीसी आयोग का गठन भी इसी मकसद से किया जा रहा है। विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा पहुंचा था, लेकिन वहां विपक्ष ने अड़ंगा लगा दिया। सरकार फिर से विधेयक लाने की बात कर रही है। खैर बात शुरू हुई थी तीन तलाक से। कांग्रेस समेत कुछ दल हैं जो सजा के प्रावधान को लेकर सवाल उठा रहे है। उन्हें फिर से सोचना होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था- 'किसी समुदाय का विकास उसमें महिलाओं के विकास से आंका जाता है।' वक्त है कि जाति धर्म से उपर उठकर मातृ शक्ति को सलाम किया जाए। ■

(लेखक दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक हैं)

विश्वस्तरीय रिसर्च पर केंद्र सरकार का जोर

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह ने 1 जनवरी 2018 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि केंद्र की राजग सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने और अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध करने के लिए विशेष ध्यान दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, नोर्वे, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम बनाए गए हैं, ताकि शिक्षा संस्थानों के संकायों को उच्चस्तरीय बनाए जा सके, शिक्षकों को अनुसंधान करने का अवसर मिले और विश्व स्तरीय उपकरणों और सुविधाओं के लिए अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों की स्थापना की जा सके। भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लागू किया है, जिनमें प्रमुख निम्न हैं-

उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई): यूएवाई योजना का उद्देश्य आईआईटी संस्थानों में नए आविष्कारों को बढ़ावा देना है, ताकि विनिर्माण उद्योगों की समस्याओं को हल किया जा सके, आविष्कार करने वाली मानसिकता को प्रोत्साहन मिले, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच समन्वय लाया जा सके तथा प्रयोगशालाओं और अनुसंधान सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा सके।

अनुसंधान, नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव (आईएमपीआरआईएनटी): समाज से जुड़े क्षेत्रों की पहचान करना है, जिसमें नवोन्मेष व वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। इस योजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए बड़ी धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अनुसंधान कार्यों के परिणाम से ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत आने वाले प्रस्तावों के लिए 50 प्रतिशत की धनराशि गृह मंत्रालय द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि संबंधित मंत्रालय/विभाग/उद्योग/गैर-गृह मंत्रालय स्रोत से उपलब्ध कराई जाएगी।

आईआईटी संस्थानों में अनुसंधान पार्कों की स्थापना: सरकार ने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बंगलुरू में पांच नए अनुसंधान पार्कों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। प्रत्येक अनुसंधान पार्क के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। आईआईटी मुंबई और आईआईटी खड़गपुर में कार्यरत दो अनुसंधान पार्कों को चालू रखने के लिए 100 करोड़ रुपये (प्रत्येक) की धनराशि स्वीकृत की गई है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने आईआईटी गांधीनगर के अनुसंधान पार्क के लिए 90 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित किया है।

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी): डिग्री और डिप्लोमा स्तर के संस्थानों के संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता को बेहतर बनाने और क्षमता निर्माण करने के लिए।

मार्गदर्शन: प्रतिष्ठित संस्थान के अंतर्गत एक हब बनाना, जो प्रौद्योगिकी संस्थानों के मध्य समन्वय स्थापित कर सके।

उच्च शिक्षा संस्थानों को विश्वस्तरीय शिक्षण व अनुसंधान संस्थानों के रूप में परिवर्तित करने के लिए 29.08.2017 को एक अधिसूचना जारी की गई और संबंधित दिशा-निर्देश 7.09.2017 को प्रकाशित किए गए।

चयनित विश्वविद्यालयों/संस्थानों को पांच वर्षों की अवधि में 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे, ताकि वे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो सकें।

9 जुलाई 2017 को ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म 'स्वयं' लांच किया गया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षण-प्रशिक्षण, स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों की पढ़ाई की जा सकती है। इसके तहत 837 पाठ्यक्रमों में कुल 16,83,828 लोग पंजीकृत हैं। डिजिटल चैनल स्वयंप्रभा के जरिए स्वयं की पहुंच का विस्तार किया गया है। ■

लोकसभा में 13 विधेयक और राज्यसभा में 9 विधेयक पारित

संसद का शीतकालीन सत्र विधायी कार्य तथा राष्ट्रीय महत्व के विविध मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिहाज से अत्यंत सफल सत्र रहा। दरअसल, संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर, 2017 को आरंभ हुआ और 5 जनवरी, 2018 को समाप्त हो गया। सत्र के दौरान 22 दिनों की अवधि में कुल 13 बैठकें हुईं। लोकसभा की उत्पादकता 91.58 प्रतिशत और राज्यसभा की उत्पादकता 56.29 प्रतिशत रही। सत्र के दौरान, 14 विधेयक (लोक सभा में) प्रस्तुत किए गए। सत्र के दौरान लोकसभा ने 13 विधेयक और राज्यसभा ने 9 विधेयक पारित किए।

केन्द्रीय संसदीय एवं रसायन व उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार तीन तलाक विधेयक एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे सभी मुद्दों पर सभी दलों से सहयोग की उम्मीद की जाती है। मंत्री महोदय ने कहा कि जैसी कि संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीपीए) की अनुशंसा है कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी, 2018 से आंरभ होगा।

दरअसल अध्यादेशों की जगह लेने वाले तीन विधेयक जैसेः माल और सेवा कर (राज्यों के लिए मुआवजे) संशोधन अध्यादेश, 2017, भारतीय वन (संशोधन), अध्यादेश, 2017 और दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 जो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए थे, पर लोकसभा द्वारा विचार और पारित किया गया था। केन्द्रीय सामान और सेवा कर नामक अध्यादेश की जगह लेने वाला (राज्यों के लिए मुआवजा) केवल एक विधेयक, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका।

इसके अतिरिक्त सत्र के अन्य मुख्य विषयों में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018 एवं कंपनी (संशोधन) विधेयक 2017, भारतीय प्रबंधन संस्थान, 2017 और भारतीय संस्थान पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017 का संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना शामिल रहा। ■

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रमुख विधेयक

- कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017
- भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017
- भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017
- निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017
- निरस्त और संशोधन विधेयक (दूसरा) विधेयक, 2017
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018

लोक सभा द्वारा पारित प्रमुख विधेयक

- निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017
- निरस्त और संशोधन विधेयक (दूसरा) विधेयक, 2017
- केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017
- स्थाई सम्पत्ति अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017 के
- केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक, 2017
- मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017
- प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थलों और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017
- उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्त) संशोधन विधेयक, 2017
- विनियोग विधेयक, 2018

राज्य सभा द्वारा पारित प्रमुख विधेयक

- कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017
- भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017
- भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017
- निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017
- निरस्त और संशोधन विधेयक (दूसरा) विधेयक, 2017
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017

सेवा क्षेत्र की दूसरी तिमाही के दौरान 7.1 प्रतिशत की वृद्धि

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 8 जनवरी को जारी वर्षांत समीक्षा-2017 की रिपोर्ट के अनुसार विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं एवं व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार और प्रसारण क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं ने 2016-17 की दूसरी तिमाही की तुलना में 2017-18 की दूसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

इस समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत सरकार की स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग बढ़ाकर बीएए3 से बीएए2 कर दी और भारत सरकार की व्यापक स्थायित्व के लिए प्रतिबद्धता जिससे कम मुद्रास्फीति, घाटे में कमी और सरकार के राजकोषीय मजबूती कार्यक्रम के क्रम में बेहतर बाह्य संतुलन को मान्यता देते हुए 13 साल बाद आउटलुक को पॉजिटिव (सकारात्मक) से स्टेबल (टिकाऊ) कर दिया।

भारत ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2017 में 130 रैंकिंग से 30 पायदान की छलांग लगाई, जो डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) रिपोर्ट, 2018 में किसी भी देश द्वारा लगाई गई सबसे ऊंची छलांग थी। इसके साथ ही ईओडीबी की इस साल की रिपोर्ट में भारत दक्षिण एशिया और ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा अकेला देश है, जिसने इतना ज्यादा सुधार दर्ज किया।

वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही के वास्तविक जीडीपी विकास के आंकड़े में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया, जो पहली तिमाही में 5.7 प्रतिशत था। दूसरी तिमाही में वास्तविक जीवीए में भी 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पहली तिमाही में 5.6 प्रतिशत थी। इस तिमाही के दौरान विकास दर को विनिर्माण में तेज बढ़ोतरी से मदद मिली, जो पहली तिमाही की 1.2 प्रतिशत की तुलना में दूसरी तिमाही में 7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई।

विद्युत और उपयोगी सेवाओं में 7.6 प्रतिशत, व्यापार, परिवहन एवं संचार में 9.9 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि से भी जीडीपी को गति मिली। समूचे सेवा क्षेत्र ने दूसरी तिमाही के दौरान 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सकल स्थायी पूंजी निर्माण की दर में भी दूसरी तिमाही के दौरान 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पहली तिमाही में 1.6 प्रतिशत रही थी। वास्तविक निजी खपत में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत के आंकड़े पर स्थिर रही।

देश की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन

- मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा भारत की स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग में 13 साल के बाद महत्वपूर्ण सुधार
- भारत ने विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में लगाई 30 पायदान की छलांग और विमुद्रीकरण की कवायद के द्वारा वित्तीय प्रणाली की स्वच्छ बनाने में मदद।
- परिवर्तनकारी सुधार-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की पेशकश के द्वारा पूरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में आमूलचूल बदलाव, जिसने कई केंद्रीय और राज्य करों की जगह ली और आयकर अधिनियम के पुनर्लेखन के लिए नई प्रत्यक्ष कर संहिता की शुरुआत की गई।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और उनके समेकन के लिए एक अल्टरनेटिव मेकैनिज्म।
- वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं-पीएमजेडीवाई और एपीवाई की भारी सफलता।
- विनिवेश के माध्यम से पूंजी जुटाने की नई पहल करते हुए सरकार ने नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), भारत 22 को पेश किया, जो सीपीएसई, पीएसबी और एसयूयूटीआई की रणनीतिक हिस्सेदारी वाले 22 स्टॉक्स का मिश्रण है।
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार सरकार का प्राथमिक लक्ष्य बना रहा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया और इसका फायदा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिला।

काले धन को अर्थव्यवस्था से निकालने के लिए 8 नवंबर, 2017 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले के एक साल बाद बड़े नोटों के सर्कुलेशन में 50 प्रतिशत तक की कमी आ गई। वेतन के लिए नकदरहित लेनदेन को सक्षम बनाने के लिए 50 लाख नए बैंक खाते खोले गए। वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2016-17 के बीच 26.6 प्रतिशत नए करदाता बढ़े। ई-रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 27.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगस्त, 2016 से अगस्त, 2017 के बीच आईएमपीएस लेनदेन की संख्या 59 प्रतिशत बढ़ी। 2.24 लाख शेल कंपनियां बंद कर दी गईं। 29,213 करोड़ रुपये अघोषित आय व देश भर में यूएलबीएस की आमदनी का पता लगा।

दूसरे विकसित देशों की तुलना में भारत में ऊंची लॉजिस्टिक लागत को ध्यान में रखते हुए एकीकृति लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास

के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 10 नवंबर, 2017 को हुई 14वीं इंस्टीट्यूशनल मेकैनिज्म (आईएम) बैठक में लॉजिस्टिक सेक्टर को इन्फ्रास्टक्चर का दर्जा दे दिया गया। इससे लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ी हुई सीमा के साथ आसान शर्तों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज उपलब्ध कराने, बाह्य व्यासायिक उधारी (ईसीबी) के तौर पर ज्यादा धन जुटाने, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों से लंबी अवधि का फंड हासिल करने और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से कर्ज लेने के लिए पात्र बनने में मदद मिलेगी।

अति महत्वपूर्ण नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) का परिचालन शुरू हो गया। एनआईआईएफ ने दीर्घकाल के लिए 1 अरब डॉलर जुटाने के लिए अबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ अपना पहला निवेश समझौता किया। ■

'इलेक्टोरल बांड्स स्कीम से एक स्वच्छ राजनीतिक युग की शुरुआत होगी'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा 2 जनवरी को संसद में चुनाव सुधार के लिए लाये गए इलेक्टोरल बांड्स स्कीम की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि यह मोदी सरकार की चुनाव सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा की नरेन्द्र मोदी सरकार चुनाव सुधार के अभियान को गति प्रदान करने के क्रम में एक और बड़ा सुधार करने जा रही है, इससे राजनीति से काले-धन के प्रवाह को ख़त्म करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

श्री शाह ने कहा कि वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने जन-आकांक्षाओं के अनुरूप चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए संसद में इलेक्टोरल बांड्स स्कीम की जो पहल की है, इससे राजनीति में पारदर्शिता आने के साथ-साथ देश में एक स्वच्छ राजनीतिक युग की भी शुरुआत हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे चुनावी चंदे के तौर पर हो रहे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में भी चुनाव सुधार के लिए इलेक्टोरल बांड्स लाने की बात कही गई थी, आज उसे संसद के पटल पर रख कर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह कहने नहीं, करने में यकीन रखती है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी राजनैतिक जीवन के अंदर शुचिता लाने और सार्वजनिक जीवन में से काले-धन के दुष्प्रभाव को निरस्त करने के लिए बड़े चुनाव सुधार कार्यक्रमों के प्रति कटिबद्ध हैं और उन्होंने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के साथ-साथ राजनीतिक पार्टियों द्वारा कैश में लिए जाने वाले चंदे को 2000 रुपये तक सीमित करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ-साथ राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में भी पारदर्शिता लाने का काम किया गया है और अब इलेक्टोरल बांड्स स्कीम आने के बाद से चुनावी चंदे को भी बैंकिंग सिस्टम में लाने का काम पूरा हो जाएगा, इससे चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में काफी मदद मिलेगी।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में चुनाव सुधार कार्यक्रमों का भी नेतृत्व करेगी, राजनीतिक जीवन में शुचिता को भी बढ़ावा देने का नेतृत्व करेगी और राजनीति से काले-धन को समाप्त करने के आंदोलन का भी नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इन तीनों विषयों को लेकर कृत-संकल्पित है। ■

'जनता कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार को स्वीकार करने के मूड में नहीं'

अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उप-चुनावों में भाजपा का उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकारें बनाने के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो विजय अभियान इस वर्ष प्रारम्भ हुआ था, वह इस वर्ष के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के उप-चुनावों में भाजपा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ जारी है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 24 दिसंबर को इस अनवरत विजय अभियान के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि कांग्रेस नेता आज मिली हार को कांग्रेस के लिए नैतिक जीत की संज्ञा नहीं देंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जनता द्वारा नकारे जाने के बाद आज अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की जनता ने भी कांग्रेस को खारिज कर दिया है। देश की जनता कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार को स्वीकार करने के मूड में बिलकुल भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हुए दोनों उप-चुनावों में भाजपा का जनाधार तेजी से बढ़ा है। आज संपन्न हुए उप-चुनाव में भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 18% हो गया है। पूर्व में हुए कांठी उपचुनावों में भाजपा 31% मतों के साथ दूसरे और कांग्रेस 1.3% मतों के साथ चौथे पर रही थी। पश्चिम बंगाल में पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ने पर मैं मैं पश्चिम बंगाल की प्रदेश इकाई और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं।

हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश के सिकन्दरा उप चुनाव में जहां भाजपा ने अपना विजय अभियान जारी रखा है, वहीं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 11.7% मतों के साथ तीसरे स्थान पर रही, इसके लिए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि सिकंदरा के चुनाव परिणाम भाजपा के प्रति किसानों और गांवों के समर्थन को दर्शाता है। इस चुनाव में बसपा द्वारा सपा की मदद से भी विपक्ष के कुप्रयासों को कोई फायदा नहीं मिला। विपक्ष के विकास-विरोधी राजनीति पर भाजपा के सुशासन का एजेंडा काफी अधिक प्रभावी है।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकारें बनाने के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो विजय अभियान इस वर्ष प्रारम्भ हुआ था, वह इस वर्ष के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के उप-चुनावों में भाजपा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ जारी है।

अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुए दोनों उप-चुनावों में भाजपा की विजय को लेकर श्री अमित शाह ने कहा कि ये सफलतायें उत्तर-पूर्व में भाजपा के बढ़ते कदमों और लिकाबाली विधानसभा में 362 मतों में सिमटने वाली कांग्रेस के पतन का प्रतीक है। उत्तर-पूर्व में भाजपा के बढ़ते कदम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी के प्रति पूर्वोत्तर की जनता के अटूट विश्वास को दिखाता है। ये चुनावी सफलतायें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा सरकार द्वारा किये जा रहे विकास पर जनता के विश्वास की मुहर है। इस वर्ष दूसरे प्रदेशों में हुए उप-चुनावों में भी भाजपा को लगातार बढ़त मिली है और कांग्रेस पार्टी लगातार घटते जनाधार के साथ हाशिये पर रही है। असम के धनजी में हुए उप-चुनाव में भाजपा ने अपना उत्तर-पूर्व का विजय अभियान जारी रखते हुए कांग्रेस को बुरी तरह हराया था।

गोवा में हुए दोनों उपचुनावों में भाजपा ने भारी जीत हासिल की थी। पणजी में भाजपा ने कांग्रेस को 31.5% मतों और वलेपी में 44.6% मतों के भारी अंतर से हराया था। राजस्थान के धौलपुर में भी भाजपा ने भारी विजय प्राप्त करते हुए कांग्रेस को 38,673 मतों से पराजित किया था। ■

भारत की विकास यात्रा आगे बढ़ती रहेगी: नरेंद्र मोदी

आमतौर पर हज-यात्रियों के लिए लाटरी सिस्टम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अकेली महिलाओं को इस लाटरी सिस्टम से बाहर रखा जाए और उनको स्पेशल केटेगरी में अवसर दिया जाए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं और ये मेरी दृढ़ मान्यता है कि भारत की विकास यात्रा, हमारी नारी-शक्ति के बल पर, उनकी प्रतिभा के भरोसे आगे बढ़ी है और आगे बढ़ती रहेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर को अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन एक समाज के रूप में हमारी पहचान पर दूर-दूर तक प्रभाव डालती रहती हैं। आज 'मन की बात' के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके साथ ऐसी एक बात शेयर करना चाहता हूं। हमारी जानकारी में एक बात आयी कि यदि कोई मुस्लिम महिला, हज-यात्रा के लिए जाना चाहती है, तो वह 'महरम' या अपने पुरुष संरक्षक के बिना नहीं जा सकती है। जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे नियम किसने बनाए होंगें? ये भेदभाव क्यों? और मैं जब उसकी गहराई में गया तो मैं हैरान हो गया- आजादी के 70 साल के बाद भी ये प्रतिबंध लगाने वाले हम ही लोग थे।

श्री मोदी ने कहा कि दशकों से मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन कोई चर्चा ही नहीं थी। यहां तक कि कई इस्लामिक देशों में भी यह नियम नहीं है, लेकिन भारत में मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं था और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ़ माइनॉरिटी अफेयर्स ने आवश्यक कदम भी उठाए और ये 70 साल से चली आ रही परंपरा को नष्ट कर के इस प्रतिबंध को हमने हटा दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मुस्लिम महिलाएं, 'महरम' के बिना हज के लिए जा सकती हैं और मुझे खुशी है कि इस बार लगभग 1300 मुस्लिम महिलाएं 'महरम' के बिना हज जाने के लिए अप्लाई कर चुकी हैं और देश के अलग-अलग भागों से- केरल से ले करके उत्तर तक महिलाओं ने बढ़-चढ़ करके हज-यात्रा करने की इच्छा ज़ाहिर की है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को मैंने सुझाव दिया है कि वो यह सुनिश्चित करें कि ऐसी सभी महिलाओं को हज जाने की अनुमति मिले जो अकेले अप्लाई कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि आमतौर पर हज-यात्रियों के लिए लाटरी सिस्टम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अकेली महिलाओं को इस लाटरी सिस्टम से बाहर रखा जाए और उनको स्पेशल केटेगरी में अवसर दिया जाए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं और ये मेरी दृढ़ मान्यता है कि भारत की विकास यात्रा, हमारी नारी-शक्ति के बल पर, उनकी प्रतिभा के भरोसे आगे बढ़ी है और आगे बढ़ती रहेगी। हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए कि हमारी महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, ताकि वे भी प्रगति के मार्ग पर एक-साथ आगे बढ़ सकें।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 अक्तूबर 2014 पूज्य बापू की जन्म जयन्ती पर हम सब ने संकल्प किया है कि पूज्य बापू का जो अधूरा काम है यानी कि 'स्वच्छ-भारत', 'गन्दगी से मुक्त-भारत'। पूज्य बापू जीवन-भर इस काम के लिए जूझते रहे, कोशिश भी करते रहे और हम सब ने तय किया कि जब पूज्य बापू की 150वीं जयंती हो तो उन्हें हम उनके सपनों का भारत, 'स्वच्छ भारत', देने की दिशा

में कुछ-न-कुछ करें। स्वच्छता की दिशा में देश भर में व्यापक स्तर पर प्रयास हो रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक जन-भागीदारी से भी परिवर्तन नज़र आने लगा है।

श्री मोदी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए आगामी 4 जनवरी से 10 मार्च 2018 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2018' किया जाएगा। ये सर्वे, चार हज़ार से भी अधिक शहरों में लगभग 40 करोड़ आबादी में किया जाएगा। इस सर्वे में जिन तथ्यों का आकलन किया जाएगा उनमें हैं– शहरों में खुले में शौच से मुक्ति, कूड़े का कलेक्शन, कूड़े को उठा कर ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था, वैज्ञानिक तरीक़े से कूड़े की प्रोसेसिंग, व्यवहार परिवर्तन के लिए किए जा रहे प्रयास, कैपिसिटी बिल्डिंग और स्वच्छता के लिए किये गए नवीन प्रयास और इस काम के लिए जन-भागीदारी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सर्वे के दौरान, अलग-अलग दल जा करके शहरों का इंस्पेक्शन करेंगे। नागरिकों से बात करके उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। स्वच्छता App के उपयोग का तथा विभिन्न प्रकार के सेवा-स्थलों में सुधार का एनालिसिस करेंगे। इसमें यह भी देखा जाएगा कि क्या ऐसी सारी व्यवस्था शहरों के द्वारा बनायी गई हैं, जिनसे शहर की स्वच्छता एक जन-जन का स्वभाव बने, शहर का स्वभाव बन जाए। स्वच्छता, सिर्फ़ सरकार करे ऐसा नहीं। हर नागरिक एवं नागरिक संगठनों की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है और मेरी हर नागरिक से अपील है कि वे, आने वाले दिनों में जो स्वच्छता-सर्वे होने वाला है उसमें बढ़-चढ़ करके भाग लें और आपका शहर पीछे न रह जाए, आपका गली-मोहल्ला पीछे न रह जाए - इसका बीड़ा उठाएं।

श्री मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि घर से सूखा-कूड़ा और गीला-कूड़ा, अलग-अलग करके नीले और हरे डस्टबिन का उपयोग, अब तो आपकी आदत बन ही गई होगी। कूड़े के लिए रीड्यूस, री-यूज़ और री-साइकिल का सिद्धांत बहुत क़ारगर होता है। जब शहरों की रैंकिंग इस सर्वे के आधार पर की जाएगी- अगर आपका शहर एक लाख से अधिक आबादी का है तो पूरे देश की रैंकिंग में, और एक लाख से कम आबादी का है, तो क्षेत्रीय रैंकिंग में ऊंचे-से-ऊंचा स्थान प्राप्त करे, ये आपका सपना होना चाहिए, आपका प्रयास होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जनवरी से 10 मार्च 2018, इस बीच होने वाले स्वच्छता-सर्वेक्षण में, स्वच्छता के इस स्वस्थ प्रतियोगिता में आप कहीं पिछड़ न जाएं - ये हर नगर में एक सार्वजनिक चर्चा का विषय बनना चाहिए और आप सबका सपना होना चाहिए, 'हमारा शहर- हमारा प्रयास, 'हमारी प्रगति-देश की प्रगति'। आइए, इस संकल्प के साथ हम सब फिर से एक बार पूज्य बापू का स्मरण करते हुए स्वच्छ-भारत का संकल्प लेते हुए पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करें।

उन्होंने कहा कि 26 जनवरी हमारे लिए एक ऐतिहासिक पर्व है, लेकिन इस वर्ष 26 जनवरी 2018 का दिन विशेष रूप से याद रखा जाएगा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सभी दस आसियान देशों के नेता मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे। गणतंत्र-दिवस पर इस बार 'एक' नहीं बल्कि 'दस' मुख्य अतिथि होंगे। ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। 2017, आसियान के देश और भारत, दोनों के लिए ख़ास रहा है। आसियान ने 2017 में अपने 50 वर्ष पूरे किए और 2017 में ही आसियान के साथ भारत की साझेदारी के 25 वर्ष भी पूरे हुए हैं। 26 जनवरी को विश्व के 10 देशों के इन महान नेताओं का एक साथ शरीक़ होना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है।

गणतंत्र-दिवस पर इस बार 'एक' नहीं बल्कि 'दस' मुख्य अतिथि होंगे। ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। 2017, आसियान के देश और भारत, दोनों के लिए ख़ास रहा है। आसियान ने 2017 में अपने 50 वर्ष पूरे किए और 2017 में ही आसियान के साथ भारत की साझेदारी के 25 वर्ष भी पूरे हुए हैं। 26 जनवरी को विश्व के 10 देशों के इन महान नेताओं का एक साथ शरीक़ होना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है।

श्री मोदी ने कहा कि यह वर्ष गुरु गोविन्द सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व का भी वर्ष था। गुरु गोविन्द सिंह जी का साहस और त्याग से भरा असाधारण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरु गोविन्द सिंह जी ने महान जीवन मूल्यों का उपदेश दिया और उन्हीं मूल्यों के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया भी। एक गुरु, कवि, दार्शनिक, महान योद्धा, गुरु गोविन्द सिंह जी ने इन सभी भूमिकाओं में लोगों को प्रेरित करने का काम किया। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। लोगों को जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने की शिक्षा दी। इन प्रयासों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ गंवाना भी पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी द्वेष की भावना को जगह नहीं दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन के हर-पल में प्रेम, त्याग और शांति का सन्देश- कितनी महान विशेषताओं से भरा हुआ उनका व्यक्तित्व था! ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि मैं इस वर्ष की शुरुआत में गुरु गोविन्द सिंह जी 350वीं जयन्ती के अवसर पर पटना साहिब में आयोजित प्रकाशोत्सव में शामिल हुआ। आइए, हम सब संकल्प लें और गुरु गोविन्द सिंह जी की महान शिक्षा और उनके प्रेरणादायी जीवन से सीख लेते हुए जीवन को ढालने का प्रयास करें। ■

यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत 25 पायदान ऊपर पहुंचा

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार के सकारात्मक प्रयासों से यात्रा व पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक (टीटीसीआई) 2017 में भारत 2013 की तुलना में 25 पायदान ऊपर पहुंच गया। टीटीसीआई रिपोर्ट 2017 में भारत का स्थान 40वां था, जबकि 2015 में यह 52वें तथा 2013 में 65वें स्थान पर था।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में जनवरी-नवम्बर 2017 में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 90.01 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए। जनवरी-नवम्बर 2015 की तुलना में जनवरी-नवम्बर 2016 के दौरान 9.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 77.83 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए।

पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में जनवरी-नवम्बर 2017 में 58.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 9.17 लाख विदेशी पर्यटक ई-पर्यटन वीजा पर भारत आए। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में जनवरी-नवम्बर 2017 के दौरान 16.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,60,865 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। 2016 के दौरान घरेलू पर्यटकों की संख्या 1613.6 मीलियन दर्ज की गई। इसमें 2015 की तुलना में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दरअसल, पर्यटकों को बेहतर पर्यटन अनुभव प्रदान के लिए पर्यटन अवसंरचना के विकास को प्राथमिकता दी गई है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत थीम आधारित पर्यटन यात्रा मार्गों को विकसित किया गया है। 2017-18 के दौरान 824.80 करोड़ रुपये की लागत से 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 5648.71 करोड़ रुपये की लागत से कुल 67 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है।

पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में जनवरी-नवम्बर 2017 में 58.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 9.17 लाख विदेशी पर्यटक ई-पर्यटन वीजा पर भारत आए। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में जनवरी-नवम्बर 2017 के दौरान 16.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,60,865 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। 2016 के दौरान घरेलू पर्यटकों की संख्या 1613.6 मीलियन दर्ज की गई।

राष्ट्रीय तीर्थस्थल पुनःस्थापना और आध्यात्मिक, विरासत विकास मिशन (पीआरएएसएचएडी) योजना के अंतर्गत तीर्थस्थलों की पहचान करके समग्र विकास करने के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 2017-18 के दौरान 98.84 करोड़ रुपये की लागत से कुल 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 587.29 करोड़ रुपये की लागत से कुल 21 परियोजनाओं को मंजूर किया गया है।

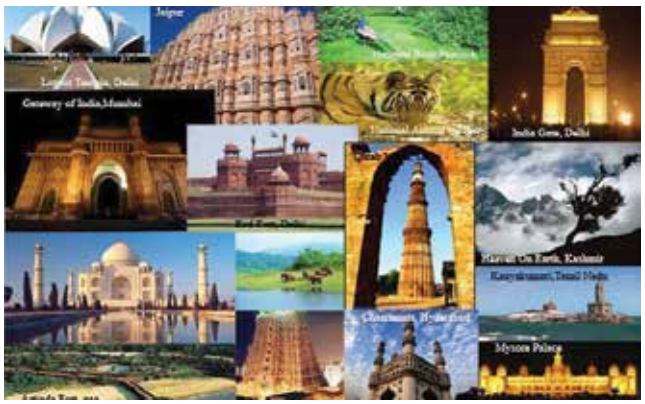

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन केन्द्रों पर विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के कार्य को प्राथमिकता में रखा है। इसके अन्तर्गत अवसंरचना का विकास, जनसुविधाएं, बहुभाषा केन्द्र तथा कौशल विकास जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। पर्यटन मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उद्योग जगत के हितधारकों के साथ मिलकर 'विरासत गोद लें' नाम से एक कार्यक्रम लांच किया है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और व्यक्तिगत स्तर पर भी इन स्थलों में सुविधाएं विकसित करने का कार्य किया जा सकता है। ऐसा करने वालों को 'स्मारक मित्र' के नाम से जाना जाएगा।

2017-18 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि राज्यों के साथ मिलकर विशेष पर्यटन क्षेत्र विकसित किए जायेंगे। राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श करके पर्यटन मंत्रालय ने इस नई योजना के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। विशेष पर्यटन क्षेत्र के निर्माण से उस क्षेत्र का समग्र विकास होगा जीविका के अवसरों का निर्माण होगा और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी।

गौरतलब है कि अक्तूबर 2017 को 31 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में पर्यटन पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन के लाभों को रेखांकित करना था। इसमें देश की सांस्कृतिक विभिन्नता को दर्शाया गया। 'सभी के लिए पर्यटन' इस कार्यक्रम की मुख्य अवधारणा थी। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड फेस्टिवल, पर्यटन प्रदर्शनी, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन, योग सत्र, पर्यटन व विरासत भ्रमण, छात्रों के लिए पर्यटन आधारित प्रतियोगिता, जागरूकता कार्यक्रम, सेमीनार और कार्यशालाएं शामिल थीं। ■

पत्र-पत्रिकाओं से...

विकास के मजबूत सहयोगी

हाल ही में नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रथम प्रवासी भारतीय सांसद सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 23 देशों के 124 सांसद और 17 मेयर शामिल हुए। इस सम्मेलन में देश के विकास में प्रवासी भारतीय सांसदों से सहयोग की नई चमकीली संभावनाएं दिखाई दीं और प्रवासियों के माध्यम से यह बात उभरकर सामने आई कि प्रवासी भारतीय सांसद नये भारत के निर्माण में आर्थिक सहभागी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रवासी भारतीय सांसद सम्मेलन में प्रवासी भारतीय सांसदों का अभिनंदन करते हुए प्रवासी भारतीयों को भारत की महान पूंजी की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने नई ऊंचाइयों को पाने के लिए तमाम देशों में संघर्ष किया है और दुनिया भर में भारत की खुशबू फैलाई है। साथ ही भारत को नई पहचान दी है।

उन्होंने कहा कि अब समय बदल गया है, भारत नई शक्ति के साथ उठ रहा है। दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष भारत की सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रवासी भारतीयों की तरफ से वर्ष 2017 में भारत में निवेश का सराहनीय सहयोग दिया गया। सम्मेलन में मोदी ने प्रवासी भारतीय सांसदों की उत्साहपूर्ण मौजूदगी में उनके सपनों का समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प व्यक्त करने के साथ प्रवासी भारतीयों से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। गौरतलब है कि प्रवासी भारतीयों को एक साझा मंच देने और उन्हें देश से जोड़ने के लिए 2003 से जनवरी माह में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर देश के उद्यमी, कारोबारी, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के द्वारा दुनिया के कोने-कोने से आए भारतवंशियों को देश के लिए लुभाने और देश के प्रति स्नेह भाव पैदा करने का प्रयास किया जाता है। प्रवासी भारतीय सांसदों के पहले सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रवासी सांसदों का आकर्षण इसलिए बढ़ा हुआ था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साढ़े तीन साल में प्रवासियों में उत्साह व देश प्रेम पैदा किया है। अपने प्रभावपूर्ण भाषण से प्रवासियों को देश से जोड़ने का प्रयास किया है। विदेशों में विभिन्न सभाओं में एक ओर उन्होंने देश में पूंजी की जरूरत के लिहाज से प्रवासियों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण बताया था। वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रवासियों की सुविधाओं के लिए अभूतपूर्व घोषणाएं भी की। स्थिति यह है कि उन्होंने जो घोषणाएं की, उन्हें सरकार ने देखते ही देखते अमलीजामा भी पहना दिया। उल्लेखनीय है कि दुनिया के करीब 200 देशों में रह रहे करीब 3.80 करोड़ प्रवासी भारतीय देश की आर्थिक-सामाजिक तस्वीर को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दुनिया के तीन देशों में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। आयरलैंड में भारतीय मूल के लिए वरदाकर, पुर्तगाल में एंटोनियो लुईस द कोस्टा और मॉरिशस में प्रविन्द जगन्नाथ प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा अमेरिका, गुयाना, पुर्तगाल में भारतीय मूल के लग कैबिनेट मंत्री भी हैं। कनाडा में 4 मंत्री भारतीय मूल के हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि विदेशों में रह रहे भारतीय कारबारियों, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्योगपतियों की प्रभावी भूमिका दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सराही जा रही है। प्रवासी भारतीय विकसित देशों के सबसे महत्त्वपूर्ण विकास सहभागी बन गए हैं। यह सर्वविदित तय है कि पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों और विदेशों में कार्य कर रही भारत की नई पीढ़ी की श्रेष्ठता को स्वीकार्यता मिली है। दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं में प्रवासी भारतीयों के योगदान का कई बार उल्लेख किया है। कहा गया है कि भारतीय प्रवासी ईमानदार, परिश्रमी और समर्पण का भाव रखते हैं। आईटी, कम्प्यूटर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, वित्त आदि के क्षेत्र में दुनिया में भारतीय प्रवासी सबसे आगे हैं। चूंकि अधिकांश प्रवासी भारतीय भारत के प्रति स्नेह और आत्मीयता का भाव रखते हैं और प्रवासियों की नई पीढ़ी भी उत्साह से भरे भावों के साथ भारत को बुलंदी पर रखने की इच्छा रखती है। स्थिति यह है कि अब प्रवासियों के सहयोग से सहभागिता की एक नई चमकीली रेखा उभरकर दिखाई दे रही है। (मुख्यांश)

— (**जयंतीलाल भंडारी**, राष्ट्रीय सहारा, जनवरी 11,2018)

स्फुट विचार...

राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम् , शिवम्, सुन्दरम् से प्रेरित है।

— **सुभाष चंद्र बोस**

इतिहास में हुई भूल के लिए आज किसी से बदला लेने का समय नहीं है, लेकिन उस भूल को ठीक करने का सवाल है।

— **अटल बिहारी वाजपेयी**

हम सदैव स्मरण रखें कि हमारी पार्टी मितव्ययता, सादगी, सेवा और समर्पणशील भावना के लिए प्रसिद्ध है। ये वे गुण हैं, जिनके कारण भाजपा अन्य पार्टियों से भिन्न पार्टी है। हम सदैव ध्यान रखें कि हमारी यह अद्भुत पहचान कभी समाप्त न हो।

— **कुशाभाऊ ठाकरे**

प्रस्तुतिः पंकज आनंद

आज ही लीजिए

कमल संदेश

की सदस्यता

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

और

दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

बेंगलुरू में संपन्न एक समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्रियों एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

बेंगलुरू में समीक्षा बैठक से पहले पुष्पांजलि अर्पित करते श्री अमित शाह

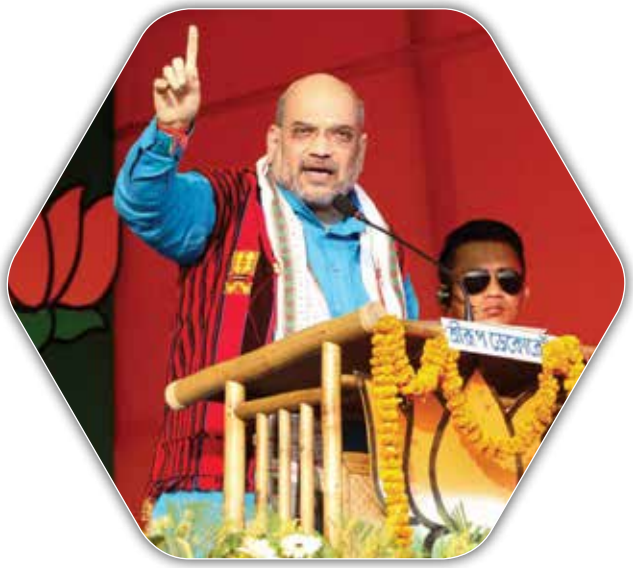

उदयपुर (त्रिपुरा) में एक विशाल रैली को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

अम्बासा (त्रिपुरा) में एक विशाल जनसमुदाय का अभिवादन स्वीकार करते हुए श्री अमित शाह

टिकरीकेला, मेघालय में जनाभिवादन स्वीकार करते श्री अमित शाह

टिकरीकेला (मेघालय) में आयोजित विशाल रैली का दृश्य

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20